संपूर्ण भारत के लिए एक प्रकाशन

RNI Reg.No.-CHHHIN/2004/15050
Postal Reg.No.-13/Surguja DN/2023-2025

दैनिक घटती घटना

Www.ghatatighatana.com
Ghatatighatana11@gmail.com

अम्बिकापुर,वर्ष 20,अंक -135 शनिवार, 16 मार्च 2024 , पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये

बिहार सरकार में कैबिनेट का हुआ विस्तार

बीजेपी से 12, जेडीयू से 9 मंत्री बनाए गए

पटना,15 मार्च 2024 (ए)। बिहार की नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार के कैबिनेट का विस्तार शुक्रवार को किया गया। मंत्रीमंडल में बीजेपी के 12 और जेडीयू के 9 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई।

इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी राजभवन में मौजूद रहे। राजभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने मंत्रियों को शपथ दिलाने की शुरुआत कर दी है।

इन्हें बनाया गया मंत्री

माहेश्वर हजारी:- माहेश्वर हजारी जेडीयू के कोटे से मंत्री बने हैं। समस्तीपुर के कल्याणपुर विधानसभा सीट से चुनाव जीते हैं। बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष के तौर पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं।

नितिन नवीन:- नितिन नवीन बिहार के कद्दावर भाजपा नेता नवीन किशोर सिन्हा के बेटे हैं। पटना की बांकीपुर सीट से लगातार चार बार विधायक का चुनाव जीत चुके हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा को शिकस्त दी थी।

दिलीप कुमार जायसवाल:- दिलीप कुमार जायसवाल बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं। बिहार बीजेपी के प्रदेश कोषाध्यक्ष के तौर पर सेवाएं दे चुके हैं। बीजेपी में पिछड़ा समाज के नेता के तौर पर पहचान रखते हैं।

नीतीश मिश्रा:- नीतीश मिश्रा बिहार के पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्रा के बेटे हैं। मिथिलांचल क्षेत्र में मजबूत पकड़ रखते हैं। बीजेपी के प्रमुख ब्राह्मण नेताओं में शुमार हैं। पिछली सरकार में भी मंत्री के तौर पर सेवाएं दे चुके हैं।

मदन सिंह:- मदन सिंह दरभंग के बहादुरपुर सीट से चुनाव जीते हैं। जिला परिषद का अध्यक्ष रह चुके हैं। अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं। मल्लाह समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। जेडीयू नेता संजय झा के करीबी हैं। 2019 में जेडीयू में जॉइन हुए। पिछली सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं।

लेसी सिंह:- लेसी सिंह पूर्णिया की धमदाहा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीती हैं। नीतीश कुमार के सिपहसलारों में एक नाम लेसी सिंह का भी आता है। बीते 24 साल में कभी भी हार का सामना नहीं किया। महिला आयोग के अध्यक्ष के तौर पर सेवाएं दे चुकी हैं। नीतीश कुमार की अगुवाई वाली पिछली सरकार में भी मंत्री थीं।

अशोक चौधरी:- नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं। बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं और जेडीयू के महादलित नेता के तौर पर पहचान रखते हैं। नीतीश कुमार की अगुवाई वाली पिछली सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। साल 2000 में पहली बार बरबीघा सीट से विधायक बने थे। जेडीयू में आने से पहले कांग्रेस में थे।

नीरज बबलू:- अपनी दबंग छवि के लिए मशहूर हैं। राजपूत जाति से हैं और सुपौल की छातापुर सीट के विधायक हैं। दिवंगत फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई हैं। पहली बार साल 2005 में राघोपुर सीट से चुनाव जीते थे।

मंगल पांडे:- मंगल पांडे विधान परिषद सदस्य हैं। बिहार बीजेपी का जाना-मान चेहरा हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और हिमाचल प्रदेश में पार्टी के प्रभारी के तौर पर सेवाएं दे चुके हैं। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर सेवाएं दे चुके हैं। बिहार बीजेपी में एक प्रमुख ब्राह्मण नेता की पहचान रखते हैं।

रेणु देवी:- रेणु देवी बेतिया से विधायक है। इस विधानसभा क्षेत्र से चार बार चुनाव जीत चुकी है। पहली बार बिहार सरकार में साल 2005 में खेल मंत्री बनाई गईं थी। नीतीश कुमार की सरकार में डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी भी संभाल चुकी हैं। दुर्गावाहिनी से राजनीतिक यात्रा शुरू की थी। बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर सेवा दे चुकी हैं।

सुप्रीम कोर्ट का रुख साफ ईवीएम से ही होंगे चुनाव

नई दिल्ली,15 मार्च 2024 (ए)। उच्चतम न्यायालय ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के कामकाज में अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली याचिका पर शुक्रवार को विचार करने से इनकार करते हुए कहा, हर पद्धति के अपने सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष होते हैं। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की एक पीठ ने कहा कि यह अदालत कई याचिकाओं की पहले ही कई मौकों पर पड़ताल कर चुकी है और ईवीएम के कामकाज से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार कर चुकी है। पीठ ने याचिकाकर्ता नंदिनी शर्मा से कहा, हम कितनी याचिकाओं पर विचार करेंगे? हाल ही में, हमने वीवीपीएटी से संबंधित एक याचिका पर विचार किया था। हम धारणाओं पर नहीं चल सकते। हर पद्धति के अपने सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष होते हैं। क्षमा करें, हम अनुच्छेद 32 के तहत इस पर विचार नहीं कर सकते।

संक्षिप्त खबर

लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज दोपहर 3 बजे

देश में लागू होगी आदर्श आचार संहिता

नई दिल्ली,15 मार्च 2024(ए)। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग आज दोपहर तीन बजे करेगा। इसके साथ ही कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान किया जाएगा।. ये विधानसभा चुनाव ओडिशा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश में होंगे। चुनाव आयोग के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी।. सूत्रों ने बताया कि लोकसभा चुनाव सात से आठ चरणों में हो सकते हैं।

रामनवमी पर रहेगा सार्वजनिक अवकाश

रायपुर,15 मार्च 2024(ए)। रामनवमी पर अब छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। राज्य सरकार ने इस संदर्भ में आदेश जारी कर दिया है। इससे पहले राज्य में रामनवमी पर सामान्य अवकाश हुआ करता था। अब ये सार्वजनिक अवकाश होगा।

सुप्रीम कोर्ट की एसबीआई को फटकार

» सीजेआई चंद्रचूड़ ने पकड़ी एसबीआई की गलती...

» बांड लेने और देने वाले के नाम...

» नंबर भी जारी करने का दिया आदेश...

» अदालत ने एसबीआई को नोटिस जारी किया और 18 मार्च तक मांगा जवाब...

नई दिल्ली,15 मार्च 2024 (ए)। चुनावी बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। कोर्ट ने एसबीआई को बांड संख्या का खुलासा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने आदेश दिया कि सीलबंद लिफाफे में रखा डेटा चुनाव आयोग को दिया जाए क्योंकि वे इसे अपलोड करना चाहते हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार यानी 18 मार्च को होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डेटा को चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बांड नंबर से यह पता चल जाएगा कि किस दानकर्ता ने किस पार्टी को दान दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार 18 मार्च को होगी। पहले इस मामले की सुनवाई आज होनी थी और इसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी होने वाली थी। लेकिन अब इस मामले की सुनवाई सोमवार को होगी।

शीर्ष चुनाव दाताओं और प्राप्तकर्ताओं की सूची,

एसबीआई और भारत निर्वाचन आयोग ने अदालत के समक्ष सभी दस्तावेज जमा किये थे। चुनाव आयोग ने गुरुवार को चुनावी बॉन्ड मामले में भारतीय स्टेट बैंक से प्राप्त डेटा को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर 763 पन्नों की दो सूचियां अपलोड की गई है। पहली सूची में चुनावी बांड खरीदने वालों का विवरण है और दूसरी सूची में राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त बांड का विवरण है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की गई सभी जानकारी 3 मूल्य वर्ग के बांड की खरीद से संबंधित है।

बांड का विवरण वेबसाइट पर जारी किया गया

सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भारतीय स्टेट बैंक ने मंगलवार शाम को चुनाव आयोग को चुनावी बांड का ब्योरा सौंप दिया। कोर्ट के आदेश के मुताबिक चुनाव आयोग को ये ब्योरा आज 15 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करना होगा। इस पृष्ठभूमि में केंद्रीय चुनाव आयोग ने कल शाम 14 मार्च को अपनी वेबसाइट पर चुनाव बांड का विवरण जारी किया है।

बिहार में शिक्षक नियुक्ति परीक्षा से पहले पेपर लीक की आशंका,300 परीक्षार्थी गिरफ्तार

रांची,15 मार्च 2024 (ए)। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित की जा रही शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में एक साथ शामिल होने जो रहे करीब 300 परीक्षार्थियों को झारखंड के हजारीबाग की पुलिस ने आज सुबह हिरासत में लिया है संदेह है कि इन अभ्यर्थियों को शिक्षक नियुक्ति परीक्षा से संबंधित प्रश्नपत्र पहले से उपलब्ध करा दिए गए थे और उन्हें हजारीबाग के दो होटलों में रुकवा कर प्रश्नों के उत्तर रटवाए गए थे।

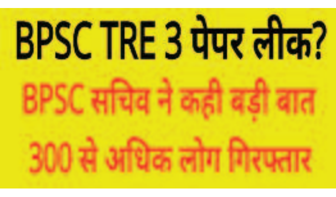

ये सभी छात्र तीन-चार बसों में सवार होकर परीक्षा देने जा रहे थे, तब हजारीबाग के बरही में इन्हें रोक लिया गया। परीक्षा शुरू हो गई है, लेकिन ये छात्र सेंटर तक नहीं पहुंच पाए। पुलिस के कई अधिकारी इनसे पूछताछ कर रहे हैं। जल्द ही बिहार के भी कुछ पुलिस अधिकारियों के पहुंचने की सूचना मिल रही है। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 15 मार्च को 2 पाली में आयोजित की जा रही है। यह बताया जा रहा है कि प्रश्न पत्र छात्रों को उपलब्ध कराने के बाद पिछले दो दिनों से पढ़ाया जा रहा था। शुक्रवार को छात्र अलग-अलग बस से परीक्षा स्थल के लिए रवाना हुए थे।सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से किसी परीक्षार्थी के पास उनका मोबाइल नहीं है। इससे पहली नजर में यह माना जा रहा है कि इन्हें परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक कराने वाले किसी गैंग के जरिए ऑपरेट किया जा रहा था। इनके मोबाइल संभवतः गैंग ऑपरेटर्स द्वारा इसलिए जब्त किए गए हैं, ताकि वे प्रश्नपत्र दूसरों से शेयर न कर सकें। इनके पास से प्रश्नों के सेट भी बरामद किए गए हैं। हिरासत में लिए गए परीक्षार्थियों में 50 से अधिक महिलाएं और लड़कियां भी हैं।

दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में के कविता गिरफ्तार

नई दिल्ली,15 मार्च 2024 (ए)। दिल्ली शराब घोटाले को लेकर ईडी तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को गिरफ्तार कर लिया है। मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में पूछताछ के लिए उन्हें हैदराबाद से दिल्ली लाया जा रहा है। जब ईडी के अधिकारी बीआरएस एमएलसी के कविता के आवास पर उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची तो बीआरएस नेता केटीआर राव और ईडी के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के एमएलसी और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को गिरफ्तार कर लिया है। पिछले साल मार्च में अरुण पिल्लई की गिरफ्तारी के बाद से ही के कविता पर भी शिकंजा कसने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा गिरफ्तारी पर रोक लगाये जाने की वजह से वह बच रही थी। 28 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने 13 मार्च तक के कविता को गिरफ्तारी से राहत दी थी।

अपाचे की गर्जना से कांपेंगे दुश्मन, सेना की ताकत में होगा इजाफा

नई दिल्ली,15 मार्च 2024 (ए)। भारत को छेड़ने की गुस्ताखी करने वालों को अब खैर नहीं...राजस्थान के जोधपुर में अपाचे हेलीकॉप्टर की पहली स्क्वाड्रन स्थापित की गई। अधिकारियों के मुताबिक, शुक्रवार को आर्मी एविएशन कोर के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अजय सूरी और बोइंग

निर्माण के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में जोधपुर में इसकी घोषणा हुई। इसकी तैनाती से पाकिस्तान की साजिश को नाकाम करने में मदद मिलेगी। भारतीय सेना ने इस मौके पर कहा कि स्क्वाड्रन का पहला हेलीकाप्टर इस साल मई के महीने में अमेरिका से आने वाला है। इस स्क्वाड्रन के गठन से पश्तिमी रेगिस्तान क्षेत्र में सेना की ताकत और मजबूत होगी। अपाचे हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी मई में शुरू होने की संभावना है। अपाचे को अमेरिकी एयरोस्पेस कंपनी बोइंग ने बनाया है और यह दुनिया के सबसे उन्नत बहुउद्देश्यीय लड़ाकू हेलीकॉप्टरों में से एक है।

सुप्रीम कोर्ट ने सिख दंगों के दोषी की फरलो याचिका पर मांगा जवाब

» इस दिन होगी मामले की अगली सुनवाई

» खोखर की उम्रकैद की सजा को दिल्ली हाई कोर्ट ने 2018 में रखा था बरकरार

» सामाजिक संबंधों को बनाए रखने के लिए फरलो की मांग कर रहे हैं: खोखर की ओर से पेश वकील

नई दिल्ली,15 मार्च 2024 (ए)। सुप्रीम कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे पूर्व कांग्रेस पार्षद बलवान खोखर की फरलो याचिका पर शुक्रवार को सीबीआइ से जवाब मांगा है। जस्टिस जेके माहेश्वरी और संजय करोल की पीठ ने सीबीआइ को नोटिस जारी करते हुए कहा कि वह सक्षम प्राधिकारी को मामले पर फैसला करने के लिए कह सकती है। खोखर की ओर से पेश वकील ने कहा कि वह सामाजिक संबंधों को बनाए रखने के लिए फरलो की मांग कर रहे हैं। पीठ ने मामले को अप्रैल महीने में आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया है।

ईडी छापेमारी का चुनावी बॉन्ड से कनेक्शन सिर्फ मान्यता पर आधारित

» चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हमें सबक लेने की जरूरत: निर्मला सीतारमण

» फंड का रोना रोने वाले राज्य रेवड़ी की करते हैं घोषणा: वित्त मंत्री

नई दिल्ली,15 मार्च 2024 (ए)। चुनावी बॉन्ड खरीदने वाली कंपनियों के नाम निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर सार्वजनिक किए जाने के बाद शुक्रवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ईडी की छापेमारी का चुनावी बॉन्ड के तहत दिए गए दान का कोई लिंक नहीं है। वित्त मंत्री सीतारमण ने क्या कुछ कहा? उन्होंने कहा कि ईडी की छापेमारी और चुनावी बॉन्ड के तहत दान को जोड़ने की जो धारणा बनाई जा रही है वह सिर्फ मान्यता पर आधारित है। उन्होंने कहा,नई दिल्ली में एक मीडिया हाउस के कार्यक्रम में वित्त मंत्री से पूछा गया था कि चुनावी बॉन्ड के तहत चंदा देने वाली 30 कंपनियों में से कम से कम 15 कंपनियों पर ईडी की छापेमारी की गई है। सीतारमण ने कहा कि यह सिर्फ मान्यता पर आधारित है कि इन कंपनियों ने खुद को सुरक्षित करने के लिए चुनावी बॉन्ड के तहत राजनीतिक पार्टियों को चंदा दिया है, क्योंकि चंदा देने के बाद भी उन कंपनियों के पास फिर से ईडी को भेजा जा सकता है।

यूपीए की प्रणाली से बेहतर था चुनावी बॉन्ड

चुनावी बॉन्ड पर पूछे गए सवाल के जवाब में सीतारमण ने कहा कि राजनीतिक दलों को चंदा के लिए वर्ष 2017 में लागू की गई चुनावी बॉन्ड प्रणाली से पहले जो प्रणाली थी वह कहीं से ठीक नहीं थी। कम से कम चुनावी बॉन्ड प्रणाली के तहत खाते से राजनीतिक पार्टियों को पैसा मिल रहा था। यह प्रणाली भी पूर्ण नहीं थी, लेकिन यूपीए की तरफ से लागू की गई प्रणाली से बेहतर थी।

राज्यों की तरफ से रेवड़ी बांटने पर मुझे कोई ऐतराज नहीं

उन्होंने कहा कि चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से निश्चित रूप से हमें सबक लेने की जरूरत है और जब कभी इसे लेकर कोई नियम बनाया जाता है या कोई प्रणाली बनती है।

बसपा और बीआरएस ने हाथ मिलाया

हैदराबाद,15 मार्च 2024 (ए)। बसपा के.चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली बीआरएस के साथ गठबंधन के तहत तेलंगाना की कुल 17 सीटों में से हैदराबाद और नगरकुर्नूल (एससी) लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। शुक्रवार को बीआरएस की एक विज्ञप्ति में कहा गया कि केसीआर ने बहुजन समाज पार्टी को दो सीटें आवंटित की हैं। जिसमें से हैदराबाद और नगरकुर्नूल (एससी) लोकसभा सीटे हैं।वहीं, बसपा की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि बसपा की तेलंगाना इकाई के अध्यक्ष आर एस प्रवीण कुमार नागरकर्नूल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। प्रवीण कुमार एक पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। विज्ञप्ति में कहा गया है कि हैदराबाद से उम्मीदवार की घोषणा जल्द ही की जाएगी। निवर्तमान लोकसभा में हैदराबाद का प्रतिनिधित्व एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं। केसीआर और प्रवीण कुमार के बीच बातचीत के बाद 5 मार्च को बीआरएस और बीएसपी ने लोकसभा चुनाव के लिए तेलंगाना में चुनाव पूर्व गठबंधन की घोषणा की। केसीआर ने तब कहा था कि विभिन्न मुद्दों पर दोनों पार्टियों के बीच वैचारिक समानता है क्योंकि उनके नेतृत्व वाली पिछली बीआरएस सरकार ने दलितों और अन्य लोगों के कल्याण के लिए दलित बंधु और अन्य योजनाएं लागू की थीं। प्रवीण कुमार ने यह दावा करते हुए कहा था कि भाजपा के कारण देश में धर्मनिरपेक्षता खतरे में है।

संपादकीय

भरोसे का नया संकट

अपेक्षित है कि चयन से संबंधित पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और ठोस रूप में मौजूद हो। उम्मीदवारों के करियर के बारे में पूरी सूचना चयन सदस्यों के पास मौजूद नहीं रहेगी, तो वे किस आधार पर उनके बारे में अपनी राय बनाएंगे?जब नए निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए संबंधित समिति की बैठक होने जा रही है, समिति के एक सदस्य का उम्मीदवारों से संबंधित विवरण मांगना इस प्रक्रिया से जुड़ी कई समस्याओं की तरफ ध्यान खींचता है। खास ध्यान समिति के सदस्य अधीर रंजन चौधरी के इस सुझाव ने खींचा है कि निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए वही प्रक्रिया अपनाई जाए, जो मुख्य एवं अन्य सूचना आयुक्तों तथा मुख्य एवं अन्य सतर्कता आयुक्तों की नियुक्ति के लिए अपनाई जाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि चौधरी के पत्र लिखने तक निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया को ही ठोस रूप नहीं दिया गया था।चौधरी लोकसभा में सबसे बड़े दल- कांग्रेस का नेता होने के नाते नियुक्ति समिति में शामिल हैं। समिति के दो अन्य सदस्य प्रधानमंत्री और उनकी तरफ से नियुक्त एक केंद्रीय मंत्री हैं। इस तरह समिति में सत्ता पक्ष का बहुमत है और वह अपनी पसंद के व्यक्तियों की निर्वाचन आयोग में नियुक्ति करवाने में सक्षम है। इसके बावजूद यह अपेक्षित है कि चयन से संबंधित पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और ठोस रूप में मौजूद हो।उम्मीदवारों के करियर के बारे में पूरी सूचना सभी सदस्यों के पास मौजूद नहीं रहेगी, तो वे किस आधार पर उनके बारे में अपनी राय बनाएंगे? क्या यह चयन प्रक्रिया के प्रति सरकार की लापरवाही को जाहिर नहीं करता कि चयन समिति के एक सदस्य को उम्मीदवारों का जीवन-परिचय मांगना पड़ा है? सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद संसदीय प्रस्ताव के जरिए निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया को बदल कर सरकार पहले ही इस बारे में काफी संदेह पैदा कर चुकी है।अब जो प्रक्रिया उसने स्थापित की है, उसको लेकर भी अगर वह अंगभीरता दिखाती है, तो निर्वाचन आयोग की साख के लिए यह अच्छी बात नहीं होगी। आयोग की साख पर पहले ही कई हलकों से गंभीर प्रश्न उठते रहे हैं। आम चुनाव से ठीक पहले एक आयुक्त के इस्तीफे को लेकर अभी भी रहस्य बना हुआ है। इस बीच अधीर रंजन चौधरी ने विधायी कार्य विभाग के सचिव को पत्र लिख कर जो मांग रखी है, उससे भरोसे का नया संकट पैदा हो गया है।

विष्णु सरकार के फैसलों से किसानों के खिले चेहरे

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में गठित छत्तीसगढ़ द्वारा मात्र तीन माह की अल्पावधि में राज्य के किसानों के हित में लिए गए फैसले से राज्य भर के किसान बेहद खुश है। उनके चेहरे खिल गए हैं और मन में एक नई उम्मीद जागी है। प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की समर्थन मूल्य पर खरीदी तथा दो साल के बकाया धान बोनस की राशि 3716 करोड़ रूपए का भुगतान होने से किसान खुश हैं।किसानों संगठनों के पदाधिकारियों का कहना है कि उन्होंने यह सोचा नहीं था कि धान खरीदी और बकाया बोनस को लेकर विष्णु देव सरकार इतनी तेजी से फैसला लेकर उसे लागू भी कर देगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी में शामिल किसानों के हित से जुड़े मामलों को जिस तेजी से छत्तीसगढ़ सरकार ने अमल में लाया है, यह स्वागत योग्य है। छत्तीसगढ़ की जनता ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी पर भरोसा जताया है। इस भरोसे को राज्य सरकार ने सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। राज्य सरकार ने राज्य के 18 लाख से अधिक पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दी है। किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी की गई है।किसानों का मानना है कि राज्य सरकार के अब तक के फैसलों से यह स्पष्ट हो गया है कि यह सरकार किसानों की हितैषी है। राज्य के किसान भाईयों को 2183 रूपए प्रति क्विंटल के मान से समर्थन मूल्य का भुगतान 48 घण्टे के भीतर उनके बैंक

खातों में किया गया है। किसानों को उनकी उपज का वाजिब मूल्य दिलाने के लिए राज्य सरकार ने कृषक उन्नति योजना के माध्यम से 24.72 लाख किसानों को धान के मूल्य के अंतर की राशि 13320 करोड़ रूपए का भुगतान का प्रदेशव्यापी शुभारंभ भी हो चुका है। भारत कृषि प्रधान देश है। देश की जीडीपी में कृषि का बड़ा योगदान है। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था का मूल आधार भी कृषि ही है और यह राज्य धान का कटोरा कहलाता है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय कहते है कि एक दौर ऐसा था जब किसानों के पास उन्नत और बेहतर खेती के लिए पूंजी नहीं होती थी। किसानों को साहूकारों से ऊंची ब्याज दर पर रकम लेकर खेती-किसानी करनी पड़ती थी। किसान हमेशा कर्ज में फंसे रहते थे। इस स्थिति को देखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने किसानों के हित में सबसे बड़ा कदम उठाया और किसान क्रेडिट कार्ड की योजना लागू की। इससे किसानों को कम दर पर सोसायटियों एवं बैंकों से कर्ज मिलने लगा। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2003 में छत्तीसगढ़ में डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व में पहली बार भाजपा की सरकार बनी, उस समय सहकारी बैंकों से किसानों को रियायती ब्याज दर पर खेती के लिए कर्ज मिलता था, जिसे धीरे-धीरे घटाकर शून्य प्रतिशत कर दिया गया। किसानों को बिना ब्याज के खेती-किसानी के लिए ऋण देने का काम छत्तीसगढ़ की रमन सरकार के दौर में शुरू हुआ था। आज भी किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर खेती के लिए लोन मिल रहा है। फसल बीमा जिसका लाभ पूरे देश के किसानों को सहजता से मिल रहा है। इसका श्रेय भी तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को जाता है। उनके कार्यकाल में ही फसल बीमा योजना का सरलीकरण किया गया। छत्तीसगढ़ में किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री सिंचाई योजना लागू की गई है। सौर सुजला योजना के माध्यम से सरकार ने दूरस्थ वनांचल में, जहां बिजली की सुविधा नहीं है, वहां किसानों के खेतों में भी इस योजना के माध्यम से सौर सुजला सिंचाई पंप स्थापित कर सिंचाई की व्यवस्था की गई है। राज्य में सिंचाई रकबे में विस्तार के लिए नवीन सिंचाई योजना के लिए 300 करोड़ रूपए, लघु सिंचाई की चालू परियोजनाओं के लिए 692 करोड़ रूपए, नाबार्ड पोषित सिंचाई परियोजनाओं के लिए 433 करोड़ रूपए एवं एनीकट तथा स्टाप डेम निर्माण के लिए 262 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है।छत्तीसगढ़ में किसानों एवं भूमिहीन मजदूरों की स्थिति में सुधार, कृषि एवं सहायक गतिविधियां के लिए समन्वित प्रयास पर राज्य सरकार का फोकस है। कृषि विभाग के बजट में बीते वर्ष की तुलना में वर्ष 2024-25 में 33 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए 13 हजार 435 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। किसानों को सहकारी एवं ग्रामीण बैंकों से ब्याज मुक्त कृषि ऋण उपलब्ध कराने के लिए 8500 करोड़ रूपए की साख सीमा छत्तीसगढ़ सरकार ने तय की है। मुख्यमंत्री सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का उल्लेख करते हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सभी वर्गों के विकास और उत्थान के लिए प्रयासरत् है। उन्होंने दूरस्थ वनांचल में रहने वाले आदिवासी भाईयों विशेषकर पिछड़ी जनजाति के लोगों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री जनमन योजना शुरू की है। छत्तीसगढ़ में निवासरत् विशेष पिछड़ी जनजातियों की बसाहटों में पक्का मकान, रोड, नाली, बिजली-पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य की बेहतर व्यवस्था के साथ ही सरकार की 11 योजनाओं का लाभ दिलाने का काम तेजी से किया जा रहा है। यह योजना छत्तीसगढ़ में 9 सरकारी विभागों के समन्वय से क्रियान्वित की जा रही है।लेखक उप संचालक हैं ।

-नसीम अहमद खान-

प्रकाशक: दैनिक घटती-घटना

जीवन के श्रेष्ठ लक्ष्य सकारात्मक श्रम और संयम से ही संभव

जिंदगी का मूल ही निरंतर संघर्ष श्रम संकल्प और प्रगति है। सकारात्मक उद्देश्य को लेकर किया गया श्रम सदैव श्रेष्ठ परिणाम देता है। श्रम और संघर्ष का कोई विकल्प ही नहीं है। निरंतर श्रम करना उच्च मनोबल बनाए रखना और सफलता की कामना और पवित्र महत्वाकांक्षा सफल मनुष्य के सच्चे मित्र होते हैं जीवन है चलने का नाम,गति का नाम ही जीवन है। सभी समाज एवं राष्ट्र की संस्कृतियों ने यह माना है कि मनुष्य और जानवरों के बीच विभेद करने वाला प्रमुख कारक मस्तिष्क है, और मस्तिष्क ही मनुष्य को सृजनात्मक शक्ति प्रदान करता है। मनुष्य के रचनात्मक विचार नयापन लाते हैं उसे पूर्व काल से पृथक करते हुए प्रगति के पथ प्रदर्शक बनते हैं। इसे ही नवप्रवर्तन माना जाता है। नवप्रवर्तन और कुछ नहीं बल्कि समाज की परंपरागत और प्रगतिशील मानसिकता के बीच एक बड़ी लाइन खींचना है। इसीलिए यह माना जाता है कि नवप्रवर्तन समाज में 3 प्रतिशत नवाचार का निर्धारित है, शेष 97 प्रतिशत परंपरावादी विचारों के लिए है। पुराने समय से ही आर्थिक समृद्धि में नवप्रवर्तन की भूमिका को स्वीकार किया गया है चाहे वह मनुष्य के खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक में परिवर्तन हो या फिर 18वीं सदी में यूरोप की वाणिज्य क्रांति का औद्योगिक क्रांति में बदलना इन सभी में नवप्रवर्तन ने प्रेरक का काम किया है। हम चौथी क्रांति की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए कहा जाता है कि विचारों को कभी सुसुप्त होने या मरने ना दिया जाए। हो सकता है आपके विचार करोड़ों डॉलर के हो । वर्तमान अर्थव्यवस्था में समृद्धि के इंजन माने जाने वाले सनराइज उद्योग, सॉफ्टवेयर, खाद्य संस्करण, इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक के विकास के पीछे भी नवप्रवर्तन का हाथ है। इसी के आधार पर नगरों को स्मार्ट नगरों में बदला जा रहा है। नवप्रवर्तन या नवाचार से मैं सिर्फ मानव जीवन की परेशानियों को न्यूनतम किया है, बल्कि मानव जीवन को आसान और सुखमय भी बनाया जा रहा है। नवप्रवर्तन और मस्तिष्क की खोज के कारण ही जापान में 6.5 रेक्टर का भूकंप सामान्य माना जाता है,जबकि भारत में यह तबाही ला सकता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में पेनिसिलिन जैसी प्रतिजैविक (एंटीबायोटिक) के अविष्कार ने रोगों की संभावना को कम कर दिया एवं स्वास्थ्य प्रणाली के भावी विकास को एक गति प्रदान की है। जेनेरिक औषधि, रोबोटिक सर्जरी, जीन एडिटिंग जैसी प्रक्रिया स्वास्थ्य सुधार हेतु एक मजबूत आधार मानी जाती है। सामाजिक विकास आर्थिक समन्वयक और न्याय प्रणाली में पारदर्शिता लाने का प्रयास नवप्रवर्तन के योगदान से ही आया है। सोशल मीडिया जैसे नवीन प्लेटफार्म ने व्यक्ति की अभिव्यक्ति के अधिकार को स्वतंत्र किया है। भारतीय अर्थव्यवस्था के ग्रामीण से आधुनिक रूपांतरण में कषि क्षेत्र से भारी उद्योगों पर बल देने में किसानों के देश को सॉफ्टवेयर उद्योग का सिरमौर बनाने में नवप्रवर्तन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारतीय कृषि में भी आधुनिकीकरण और पाश्चात्य उपकरण का प्रादुर्भाव भी नवीन नवाचार के कारण संभव हुआ है। भारतीय राज्य को लोक कल्याणकारी राज्य से लोगों के सशक्तिकरण करने वाले राज्य में बदलने की नवप्रवर्तन की भूमिका अत्यंत सराहनीय है। इसके कारण भार मानी जाने वाली महिलाएं अब भार ढोने वाली की भूमिका में आ चुकी हैं। इसी तरह न्यायिक क्षेत्र में जनहित याचिका की अवधारणा ने न्याय की अवधारणा को सर्वांगीण बनाने में सहायता प्रदान की है। यह अलग बात है कि केवल नवप्रवर्तन को ही एकमात्र निर्धारक कारक के रूप में नहीं माना जा सकता क्योंकि नवीन विचारों को स्वीकार करना और आगे बढ़ना बहुत हद तक समाज पर निर्भर करता है। पश्चिमी देशों में नवीन विचारों को जगह देने के कारण वहां पुनर्जागरण आया है। हमें समाज को नव परिवर्तन की तरफ जागरूक करने की आवश्यकता होगी और नवप्रवर्तन में ज्यादा से ज्यादा आर्थिक मदद देकर उस और और ज्यादा विचार-विमर्श कर नीति बनाने की आवश्यकता होगी। इस तरह हमें महात्मा बुद्ध के कथन अनुसार अपने या दूसरों के विचारों नवप्रवर्तनों को तर्क बुद्धि पर देखे जाने की जरूरत है, और फिर आगे बढ़ने का प्रयास किया जाना चाहिए।

संजीव ठाकुर,
रायपुर छत्तीसगढ़,

प्रकाशक: दैनिक घटती-घटना

भाजपा की मंडी में सुरेश पचौरी

सुरेश पचौरी को खरीदा नहीं गया होगा। इसलिए क्योंकि बुढ़ापे में भला उनका मूल्य क्या है? मान्यता है कि बूढ़े नेता और बूढ़ी वेश्या का बुढ़ापा एक सी मनोव्यथा में होता है। दोनों संताप, लाचारगी और भूख में फडफ़ड़ाते होते हैं। क्या होती है दोनों की मनोव्यथा? इस बात का संताप की कभी वह कोठे की हूर, सत्ता का जलवा लिए हुए थे। तब सब लोग आगे-पीछे घूमते थे। वाह-वाह करते थे। दलालों से घिरे रहते थे। पैसा बरसता था। शाही ठाठ था। तूती बोलती थी। वैभव और जलवा था। यह जो जलवा' शब्द है वह सत्ता के गलियारे के नेताओं और कोठे में जवानी के ठसके वाली वेश्या को तब भीतर ही भीतर गलाता है जब वह पॉवर और जवानी से आउट होते हैं। तब वैभव के दिनों को याद करते हुए इस संताप में रहते हैं कि कभी मेरे आगे-पीछे दुनिया घूमती थी। कोठी और कोठे पर भीड़ होती थी। हर कोई एक झलक के लिए, इनायत के लिए तरसता था। वे कैसे अच्छे दिन थे और अबज.बुढ़ापा कटे तो कैसे कटे !कांग्रेस ने कोई पचपन साल राज किया। सत्ता की दिल्ली कोठियां कांग्रेसियों से भरी हुई थीं। सत्ता और जवानी के मजे लिए। लोगों को बेवकूफ बनाया। वैभव और जलवे से जीये ! पर अंतत- बुढ़ापा। जनता का मन भरा। और उनकी जगह नरेंद्र मोदी और भाजपा की ताजगी, जवानी पर लोग फिदा हुए तो सोचें कांग्रेसियों के बूढ़े चेहरों की मनोदशापर । एसएम कृष्णा, गुलाम बनी आजाद आदि, आदि। और अब सुरेश पचौरी।कुछ दिन पहले ही मिले थे। पर मुझे रत्ती भर अनुमान नहीं हुआ कि वे भीज.। उन्हें कांग्रेस ने 1981 से लेकर 2011 की अवधि में इंदिरा, राजीव, सोनिया गांधी की कांग्रेस ने क्या नहीं दिया ! 24 साल याकि चार टर्म राज्यसभा सांसद थे। कार्मिक, रक्षा जैसे अहम मंत्रालय में मंत्री रहे। सोनिया गांधी और अहमद पटेल के सबसे विश्वस्त।पर कल मैंने जब उन्हें भाजपा की मंडी में देखा तो मुझे हिंदुओं की इस राजनीति पर घिन हुई। समझ नहीं आया मोदी-शाह ने पचौरी का क्या मूल्य लगाया होगा? और पचौरी ने क्या चाहते हुए भगवा पहना? ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। भारत में सत्ता से बाहर हुए नेता

(किसी भी पार्टी का) को तो बस सत्ता के मेले का, भर्ती मेले का इंतजार रहता है। भला सत्ता के नशे के बिना कैसे जिंदगी गुजरे। तभी तो राजनीति और वेश्यावृत्ति को एक जैसा माना जाता है।हां, हिंदुओं को हजार साल पहले राजा भर्तृहरि द्वारा उद्घाटित इस सत्य को याद रखना चाहिए कि, वारांगना इव नृपनीति'। मतलब राजनीति, वेश्या है। इस नीति श्लोक का पूरा खुलासा यह है कि- कभी सत्य, कभी झूठ, कभी मिथ्या, कभी कटुभाषिणी और कभी प्रियभाषिणी, कभी हिंसा और कभी दयालुता, कभी लोभ और कभी दान, कभी अपव्यय और कभी धन संचय करने वाली जैसे वेश्या होती है उसी भांति राजनीति भी अनेक रूप धारण कर लोगों को लुभाती है, मूर्ख बनाती है। (वारांगनेव नृतनीतिरनेकरूपा।

सत्यानृता च परुषा प्रियवादिनी चहिंस्त्रा
दयालुरपि चार्थपरा वदान्या। नित्यव्यया
प्रचुरनित्यधनागमा चवाराङ्गनेव
नृपनीतिरनेकरुपा'।

-भर्तृहरि नीति शतक श्लोक 47)और मालूम है हाल के वर्षों में राजनीति और वेश्या का ज्ञान किसने बघारा था? आरएसएस के सुप्रीमो कुप सी सुर्दशन ने। उन्होंने राजनीति को वेश्यावृत्ति समान तब बताया था जब लालकृष्ण आडवाणी ने जिन्ना की मजार पर जिन्ना की प्रशंसा की थी। उस पर बवाल हुआ तो डॉ. वेदप्रताप वैदिक का लिखना था- सुदर्शनजी ने कुछ गलत नहीं कहा। जऐसा कहनेवाले भर्तृहरि थे। वे स्वयं राजा थे। वे अपनी नृपनीति' की विसंगतियां उजागर कर रहे थे। वे वेश्या की अम्मा नहीं थे।जनसंघ और भाजपा तो संघ की बेटियां हैं। संघ उनकी अम्मा है। मां अपनी बेटियों के बारे में कुछ भी कहे तो बेचारी बेटियां क्या बोल सकती हैं? वे तो चुप हैं। उन्हें चुप रहना ही सिखाया गया है लेकिन भाजपा की यह चुप्पी न केवल उसके लिए अपितु राष्ट्रीय राजनीति के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। गोवा में जो हुआ, वह इससे भी ज्यादा भीषण है। पैसों और पदों के खातिर कौन नेता और कौन दल कब शीर्षासन की मुद्रा धारण करेगा, कुछ नहीं कह सकते। सत्ता की खातिर कांग्रेस कब भाजपा बन जाएगी और भाजपा कब कांग्रेस बन जाएगी, कोई नहीं जानता। सोचें, भर्तृहरि, सुदर्शन तथा डॉ. वेदप्रताप वैदिक के कहे में आज की सच्चाई क्या है? पूरा देश खरीद-फरोख्त की वह मंडी है, जिसमें दीन-ईमान सब बिकता है। लोगों के दीन-ईमान को मजबूर किया जाता है कि वह बिके जैसे वेश्याओं को जिस्म बेचने के लिए मजबूर किया जाता है। कहीं कोई चरित्र नहीं। इंच भर धर्म-ईमान नहीं है और हल्ला है रामराज्य का!सवाल है जिस राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ के प्रमुख ने आडवाणी जैसे नेता को आईना दिखाया था वह भाजपा की खुली मंडी, खरीद-फरोख्त से कैसे गौरवान्वित है? पर यह फैसला करना मुश्किल है कि संघ गौरवान्वित है या शर्मसार? शायद जवाब हो कि कांग्रेस भी ऐसा ही करती थी। आयाराम-गयाराम, दलबदल सब कांग्रेस के समय से होता आ रहा है। और नीति शतक कहता ही है कि वेश्या मतलब राजनीति, राजनीति मतलब वेश्या है तो नियति के आगे हम अपने चाल, चेहरे, चरित्र से क्या कर सकते हैं।ठीक बात है। गुलाम इतिहास से संस्कारित हिंदुओं का हजार साल से यही रोना है कि हमारे बस में क्या? जैसे प्रभु रखेंगे वैसे रह लेंगे।शायद यही सोच है, जिसके कारण भारत में किसी को दीन-ईमान बेचने या खरीदने में रत्ती भर संकोच नहीं होता। आखिर व्यक्ति जब दिन-रात सत्ता के नशे में धुत हुआ रहता है तो उसे बिना नशे के चैन मिल ही नहीं सकता। भारत और दुनिया के सभ्य लोकतांत्रिक देशों का यही फर्क है जो वहां राजनीति एक प्रोफेशन है, लोक प्रशासन है, जबकि भारत में सत्ता की भूख है, रूतबा है। हिंदुओं ने हजार साल विदेशी शासकों, विधर्मी शासन की ताबेदारी और कोतवाल व्यवस्था में भयाकुल जीवन जीया है तो बूझ सकते हैं दिल-दिमाग में सत्ता की भूख कितनी पैठी हुई है?कोई भले इस बात को न माने लेकिन मेरा मानना है कि अंग्रेजों से 15 अगस्त 1947 को हमें जो आजादी मिली थी वह हम देशज लोगों की इस भूख, छटपटाहट को लिए हुए थी कि बस जैसे भी हो हमें फटाफट पॉवर चाहिए। तभी अंग्रेजों से वह भारतीयों को पॉवर ट्रांसफर था। तभी न अंग्रेजों की बनाई व्यवस्था बदली और न दिल्ली का सत्ता चरित्र बदला। उलटे सर्वजनों में अधिकार के नाम पर पॉवर की बंदरबांट हुई। वह कुछ भी नहीं हुआ, जिससे चरित्र बने। संस्कार, नैतिक मूल्य बने। भाईचारा और समानता बने।त्रासद सत्य है कि एक तरफ लोकप्रियता के पीक के बावजूद खरीद-फरोख्त के लिए हर संभव तिकड़म है वही चालीस-पचास साल लगातार पॉवर भोगने के बावजूद नेता लोग बिकने को तैयार। धोखा देने, अहसानफरामोशी के लिए तत्पर। इसलिए क्योंकि जीवन भर जब कोठी-कोठे में जलवे से जीवन जीया गया है तो वे बेचारे बुढ़ापा कैसे सड़क पर गुजारें।सब कुछ होते हुए भी पॉवर में रहा व्यक्ति भारत में बिना पॉवर सड़क का लावारिस होता है। करे क्या वह, कोई पूछता नहीं। कभी ग्राहकों की भीड़ थी और अब कोई झांकता भी नहीं है तो उसे सत्ता की मौजूदा दुकान के आगे कटोरा ले कर खड़ा ही होना होगा।तब नेता बिरादरी की इस फडफ़ड़ाहट को भला गुजरात की धंधे की तासीर में पले-बढ़े नरेंद्र मोदी और अमित शाह क्यों न भुनाएं? इसलिए भर्ती मेला कहें या मंडी, सबको न्योता है, आओ अपना ईमान बेचो।तभी दस वर्षों से रेला लगा हुआ है। न विचार की वफादारी है और न ईमान की, न ही अहसान की। कुल मिलाकर सत्य क्या? राज किसी का भी हो, भारत की राजनीति सदा-सर्वदा वारांगना (वेश्या) है। समय के साथ उसमें विस्तार है और रामराज्य व अमृतकाल की तो वह इतिहासजन्य विशिष्टता है। क्या नहीं?

-हरिशंकर व्यास-

प्रकाशक: दैनिक घटती-घटना

अटकाव

ताबीज तब ही काम आते हैं
जब बोलने की तमीज हो।
वक्त तब ही काम आता है
जब वक्त की कदर की हो।
अजीज तब ही काम आते हैं
जब उनसे तहबीज हो।
भक्ति तब ही काम आती है
जब उसमें शक्ति जगाई हो।
अपने तब ही काम आते हैं
जब उनसे अपनापन रखा हो।
इंसान तब ही काम आते हैं
जब उनमें इंसानियत बची हो।
दिल्लगी तब ही काम आती है
जब दिलदार अपना हो।

डॉ.राजीव डोगरा
जनयानकड़
कांगड़ा
हिमाचल प्रदेश

प्रकाशक: दैनिक घटती-घटना

मुक्तक

जब-जब मैंने खुद को
अकेला पाया है मैंने,
हर बार तुने समझाया है,
हमारे रिश्ते को बचाया है,
तुने बड़े प्यारे से
इस रिश्ता निभाया है

मुस्कान केशरी
मुजफ्फरपुर
बिहार

प्रकाशक: दैनिक घटती-घटना

तू जरा मुस्कुरा के चल

मंजिल तुझसे दूर नहीं होगें,
खुद पर विश्वास जगा के चल।
सारे अरमान तेरे पूरे होगें,
तू जरा मुस्कुरा के चल।।
आंधियों से कभी मत डर,
इसे पैरो तले दबा के चल।
लक्ष्य पर अपना फोकस कर,
तू जरा मुस्कुरा के चल।।
राहों में समस्याएं आएगी,
इसका जरूर निकलेगा हल।
जीत तेरी पक्की होगी,
तू जरा मुस्कुरा के चल।।
ख्वाब हकीकत में बदलेगा,
आज नही तो कल।
कामयाबी तेरे कदम चूमेगा,
तू जरा मुस्कुरा के चल।।

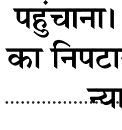

श्याम सुंदर साहू
राजिम जिला
गरियाबंद
छत्तीसगढ़

प्रकाशक: दैनिक घटती-घटना

सीएए नियमों के बाद बदल रहे टकराव के स्वरूप

धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण अब नियम है।क्योंकि कानून बदल गया है। नागरिकता चुनिंदा देशों के चुनिंदा श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है, जब तक कि 2019 नागरिकता संशोधन अधिनियम और अब अधिसूचित नियमों के तहत आवेदक मुस्लिम नहीं है। मुसलमानों को पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से अलग करने वाली रेखा वहां बहुसंख्यक समुदाय के रूप में उनकी स्थिति है। हिंदू, सिख, जैन, पारसी और बौद्ध, वहां अल्पसंख्यक के रूप में, सीएए और सीएआर के अंतर्गत आते हैं। स्पष्ट कथन स्वयं को यह बताने जैसा है कि भारत में धर्म के आधार पर भेदभाव अब कोषेर है, हालांकि संविधान स्पष्ट रूप से इस तरह के भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। अनुच्छेद 15 में यह स्पष्ट था कि राज्य केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर किसी भी नागरिक के खिलाफ भेदभाव नहीं करेगा। जिस क्षण सीएए के नियम लागू हुए, उस समय ऐसा प्रतीत हुआ कि भारत

धर्मनिरपेक्ष से किसी और चीज़ की ओर स्थानांतरित हो रहा है, जो समय के साथ हिंदू राष्ट्र जैसा दिखने लगेगा, जिसकी कर्नाटक भाजपा के एक प्रमुख नेता अनंत कुमार हेगड़े बहुत प्रबल इच्छा रखते हैं।

भारत की पहचान में धर्मनिरपेक्ष से किसी और चीज़ की ओर विवर्तनिक बदलाव 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए उपयुक्त है। नरेंद्र मोदी सरकार अपनी 2019 की गारंटी को पूरा कर रही है कि नए नागरिकता नियम उन इलाकों को लक्षित करते हुए लागू किए जाएंगे जहां बड़ी संख्या में हिंदू बांग्लादेश से आए थे,खासकर पश्चिम बंगाल,त्रिपुरा,असम,मेघालय और पूर्वोत्तर में अन्य जगहों पर। अधिसूचना इस बात की पुष्टि थी कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो अपने वादे पूरे करती है।

केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल,सपा प्रमुख अखिलेश यादव, सीताराम येचुरी और मल्लिकार्जुन खड़गे और छोटे और क्षेत्रीय दलों की ओर से आई प्रतिक्रियाओं से ध्रुवीकरण स्पष्ट है। इंडिया गुट नागरिकता कानून में बदलाव के खिलाफ है, जबकि बीजेपी इसकी सफलता पर खुशी मना रही है। परिवर्तन का असर अन्य राज्यों की तुलना में पश्चिम बंगाल और असम की राजनीतिक गतिशीलता पर अधिक पड़ेगा। जबकि पश्चिम बंगाल में इसे लागू करना सीधा है, असम में इसने बंगाली भाषियों की उपस्थिति के प्रति हिंसक रूप से शत्रुतापूर्ण जातीय समूहों द्वारा विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है, चाहे वे हिंदू हों या मुस्लिम। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा भले ही विरोध को गुमराह बताने की कोशिश करते हों, लेकिन सच्चाई यह है कि बंगाली भाषियों को नागरिकता देने का भाजपा का कदम ध्रुवीकरण कारक है, न कि आवेदकों की धार्मिक पहचान।

पश्चिम बंगाल में, ममता बनर्जी ने भले ही बदलाव को लॉलीपॉप कहकर खारिज कर दिया हो, लेकिन वह इस संभावना के प्रति सतर्क थीं कि 10 मार्च को ऐसा कुछ होगा, जब उन्होंने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक मेगा रैली को संबोधित किया था। उन्होंने चेतावनी दी कि पश्चिम बंगाल में किसी भी हिरासत केंद्र की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने सीएए और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर गणना प्रक्रिया के कार्यान्वयन को रोकने की कसम खाई। सुश्री बनर्जी का तर्क है कि सीएए अनावश्यक है। बांग्लादेश से आए अनुसूचित जाति मतुआ समुदाय के हिंदुओं के पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड हैं, वे सरकार और रक्षा सेवाओं में काम करते हैं, और विधायक, सांसद और पंचायत और नगर निकाय के सदस्यों के रूप में चुने गए हैं।

-शिखा मुखर्जी-

प्रकाशक: दैनिक घटती-घटना

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।

छात्रा की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने युवती को किया गिरफ्तार

- संवाददाता -
अंबिकापुर, 15 मार्च 2024 (घटती-घटना)।

3 माह पूर्व इंस्टाग्राम में फोटो पोस्ट कर अश्लील टिप्पणी किए जाने से दुष्प्रेरित होकर छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में दोषी पाए जाने पर मणिपुर पुलिस ने एक युवती को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी युवती के खिलाफ कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है।

पुलिस के अनुसार एक छात्रा मणिपुर थाना क्षेत्र के मठपारा में अपने मामा के घर में रहकर पढ़ाई करती थी। तीन माह पूर्व इसके मामा-मामी घर में नहीं थे। इस दौरान मृतका अपनी बड़ी बहन के साथ यहां थी। 12 दिसंबर की रात को छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस मर्ग कायम कर मामले की जांच कर रही थी। जांच में पाया गया कि आरोपी ममता इ्क्षसह द्वारा इंस्टाग्राम में मृतका का फोटो अपलोड कर अश्लील टिप्पणी की थी। इसे दुष्प्रेरित होकर छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में पुलिस ने ममता इ्क्षसह को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ धारा 305 व 67 आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है। कार्रवाई में प्रधान आरक्षक सतीश सिंह, आरक्षक सुरेश गुप्ता, अतुल शर्मा, नीलम यादव शामिल रहे। पुलिस ने बताया कि 10 दिसंबर 2023 को आरोपी ने मृतका छात्रा का फोटो के साथ टैग कर अश्लील टिप्पणी की थी। मृतका व ममता में पूर्व से जान पहचान था। मृतका का एक लडक़े से जान पहचान थी। उसी लडक़े से आरोपी युवती का भी जान पहचान था। आरोपी लडक़ी उस लडक़े से शादी करनी चाहती थी। इसी बीच आरोपी लडक़ी को पता चला की उसी लडक़े से मृतका का भी पहचान है और दोनों घुमने गए हुए हैं। यह बात ममता इ्क्षसह को अच्छा नहीं लगा और मृतका का फोटो इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर अश्लील टिप्पणी की थी।

मुख्यमंत्री से अंबिकापुर को फोरलेन सडक़ से जोडऩे की मांग

» **रायपुर से अंबिकापुर होते हुए वाराणसी तक फोरलेन सडक़ से जुडऩा,व्यापक जनहित में सरगुजा क्षेत्र के विकास में क्रांतिकारी कदम होगा:अखिलेश सोनी**

- संवाददाता -
अंबिकापुर, 15 मार्च 2024 (घटती-घटना)।

भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य एवं पूर्व जिला अध्यक्ष अखिलेश सोनी ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंप कर अंबिकापुर को फोरलेन सडक़ से जोडऩे की मांग की है। मुख्यमंत्री को सौंपे ज्ञापन में अखिलेश सोनी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश वाराणासी एवं नागपुर दो महत्वपूर्ण शहरों के मध्य स्थित है। दोनों शहरों का महत्व अनेकानेक कारणों से छत्तीसगढ़ के लोगो के लिए अत्यधिक है। नागपुर से वाराणासी की दूरी लगभग 935 किमी है। नागपुर से रायपुर एवं बिलासपुर होते हुए कटघोरा तक तथा रेनुकुट (हाथी नाला) से वाराणासी तक भी 4 लेन सडक बनी हुई है। कटघोरा से रेनुकुट (हाथी नाला) की दूरी लगभग 270 किमी है, जो 4 लेन सडक नहीं है एवं सम्पर्क अत्यन्त असुविधाजनक है। यदि भारत माला परियोजना या अन्य योजनाओं के तहत कटघोरा से रेनुकुट (हाथी नाला) तक 4 लेन सडक का निर्माण कर दिया जाये, तो वाराणासी (उप्र) से रेनुकुट, होते हुए छग के अम्बिकापुर, बिलासपुर-रायपुर दुर्ग-राजनांदगांव से नागपुर शहर (महाराष्ट्र) 4 लेन एक्सप्रेस वे से जुड़ जायेगा। फोरलेन के संदर्भ में मुख्यमंत्री से चर्चा में उन्होंने कहा कि रायपुर से अंबिकापुर होते हुए वाराणसी तक फोरलेन सडक़ से जुडऩा, व्यापक जनहित में सरगुजा क्षेत्र के विकास में क्रांतिकारी कदम होगा, उक्त स्वीकृति से छत्तीसगढ़-उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के मध्य बहुआयामी विकास के मार्ग भी खुलेंगे। प्रभु राम की नगरी अयोध्या एवं बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणासी से नागपुर के मध्य छत्तीसगढ़ के जनजातीय बाहुल्य सरगुजा सम्भाग अन्तर्गत राम वन गमन के कई महत्वपूर्ण स्थल आते है। रामगढ़, शिवपुर, महेशपुर, सीता बेंगरा, मैनपाट, रतनपुर की महामाया, डोंगरगढ़ जैसे प्रमुख ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटक स्थलों को भी यह मार्ग जोड़ेगा। व्यापार, संस्कृति, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि विषयों में तीनों प्रदेश के लोग लाभान्वित हो सकेंगे। व्यापक जनहित को देखते हुए उन्होंने छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर को वाराणासी तक 4 लेन सडक़ से जोडऩे के लिए कटघोरा से अम्बिकापुर होते हुए उत्तर प्रदेश के रेनुकुट (हाथी नाला) तक 4 लेन सडक़ (एक्सप्रेस वे) के निर्माण की स्वीकृति प्रदान करने का मुख्यमंत्री से निवेदन किया है। मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने के दरमियां पूर्व सांसद कमलभान सिंह मौजूद रहे।

चोरी के मामले में चार आरोपी भिलाई से गिरफ्तार, कार से आकर दिए थे वारदात को अंजाम

- संवाददाता -
अंबिकापुर, 15 मार्च 2024 (घटती-घटना)।

चोरी के मामले में गांधीनगर पुलिस ने चार आरोपियों को भिलाई से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चारो आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है।

पुलिस के अनुसार अशोक मिश्रा गांधीनगर थाना क्षेत्र के भगवानपुर कला का रहने वाला है। 24 जनवारी को वह सह परिवार अपने गांव एमपी गया था। 27 जनवरी को पड़ोसी ने मोबाइल से जानकारी दी कि आपके घर का ताला टूटा हुआ है। सूचना पर आरक्षक परिवार सहित घर पहुंचा तो मकान का ताला टूटा था। अंदर सामान बिखरा पड़ा था। आलमारी का लॉक टूटा हुआ था। आलमारी में सोने-चांदी के जेवरात व नगदी 5 हजार रुपए नहीं थे। इस दौरान चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर भी अपने साथ ले गए थे। खनिज विभाग के आरक्षक ने मामले की रिपोर्ट गांधीनगर थाना में दर्ज कराई थी। पुलिस अज्ञात के खिलाफ अपराध दर्ज कर मामले की जांच कर रही थी। विवेचना के दौरान सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपियों तथा घटना में प्रयुक्त कार की पहचान की। इसके बाद पुलिस ने दुर्ग व रायपुर जाकर स्थानीय पुलिस के सहयोग से खुर्सीपार, शारदापारा कैम्प-2 भिलाई निवासी विक्की वर्मा को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो वह अपने नरेन्द्र सिंह उर्फ बिट्टू निवासी छावनी चौक, थाना जामुल, भिलाई, इलियास निवासी गोकूलनगर, टिकरापारा रायपुर व समीर खान निवासी मोतीनगर, बिजनगर, टिकरापारा रायपुर के साथ वारदात को अंजाम देने की बात स्वीकार की। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर अंबिकापुर लाकर इनके खिलाफ कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद कार से वापस भिलाई लौटने के क्रम में सीसीटीवी कैमराा का डीवीआर को रास्ते में चलती वाहन से पानी में फेंक दिया था। वहीं मुख्य आरोपी विक्की वर्मा के खिलाफ विभिन्न थानों में चोरी व आबकारी एक्ट का मामला दर्ज है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त कार, बाइक, चार नग मोबाइल, टूटा हुआ ताला, रॉड व नकदी 31 सौ रुपए जब्त किया है।

47 लीटर महुआ शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार

- संवाददाता -
अंबिकापुर, 15 मार्च 2024 (घटती-घटना)।

लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आबकारी विभाग के उड़दस्ता टीम द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में शुक्रवार को कोतवाली क्षेत्र के ग्राम नावागढ़ निवासी एक व्यक्ति के कब्जे से 47 लीटर महुआ शराब जब्त किया है। वहीं टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है।

सहायक जिला आबकारी अधिकारी रंजीत गुप्ता ने बताया कि मुखबिर से जानकारी मिली रही थी कि कोतवाली क्षेत्र के नावागढ़ निवासी संजीव उरांव अपने घर में महुआ शराब तैयार कर बिक्री करने का काम कर रहा है। शुक्रवार को आबकारी विभाग के उडऩ्दस्ता टीम कार्रवाई के लिए उसके घर पहुंची तो संजीव स्कूटी से कहीं जा रहा था। सकी स्कूटी की तलाशी ली गई तो 17 लीटर महुआ शराब पाया गया। वहीं उसके घर 30 लीटर शराब जब्त किया गया। कुल मिलाकर संजीय उरांव के कब्जे से 47 लीटर महुआ शराब जब्त किया गया है। टीम ने संजीव को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) क, 34(2) एवं 59 (क) के तहत कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है। इस दौरान कार्रवाई में आरक्षक रमेश दुबे, अशोक सोनी, रामाधार कुशवाहा, नगर सैनिक गणेश पांडे, रणविजय सिंह एवं महिला सैनिक राजकुमारी एवं ममता उपस्थित रहे।

चोरी की बाइक के साथ एक आरोपी गिरफ्तार

- संवाददाता -
अंबिकापुर, 15 मार्च 2024 (घटती-घटना)।

चोरी की बाइक के साथ पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है। जानकारी के अनुसार संदीप कुमार गांधीनगर का रहने वाला है। 25 फरवारी की शाम को अपनी बाइक से गांधी स्टेडियम टहलने गया था। इस दौरान वह अपनी बाइक को स्टेडियम के बाहर खड़ा किया था। कुछ देर बाद जब वह वापस जाने निकला तो उसकी बाइक चोरी हो गई थी। वह मामले की रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज कराई थी। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी रोहित सिंह पावले पिता स्व. बोधन सिंह पावले उम्र 24 वर्ष, निवासी बरपारा, लांद चौकी कोरबी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी की बाइक भी जब्त की है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है।

यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित बनाये रखने में ऑटो चालकों की भूमिका महत्वपूर्ण

- संवाददाता -
अंबिकापुर, 15 मार्च 2024 (घटती-घटना)।

सरगुजा पुलिस द्वारा जिले की यातायात व्यवस्था को सरल, सुगम एवं सुरक्षित बनाने के दिये गये निर्देश के परिपालन में ऑटो चालकों की मीटिंग ली गई। जिसमें ऑटो चालकों को समझाइश दी गई की शहर की यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित बनाये रखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आप लोगों का ही होता है। किसी अन्य जिले से कोई व्यक्ति बस स्टैण्ड, रेल्वे स्टेशन पहुंचता है तो वह सर्वप्रथम उसे अपने गंतव्य स्थान पर जाने के लिए आप लोग का ही सहयोग लेना होता है। यदि आप लोग उन लोगों से मधुर व्यवहार एवं निर्धारित शुल्क वसूल करते हो और अपने वाहन को क्रमबद्ध निर्धारित पार्किंग, स्थान पर खड़ा करते हो जिससे उस व्यक्ति के मन में जिले के प्रति एक अच्छी छवि बनती है।

मीटिंग के दौरान यातायात पुलिस द्वारा उपस्थित 70 ऑटो चालकों को व्यक्तिगत छवि के साथ-साथ यातायात नियमों जैसे बिना वर्दी वाहन न चलाना, शराब एवं किसी भी नशीली पदार्थ का सेवन कर वाहन न चलाना, नाबालिक को वाहन चलाने न देना, निर्धारित क्षमता से अधिक सवारी न बैठाना, वाहनों का दस्तावेज दुरूस्त रखना, निर्धारित पार्किंग, स्थान पर ही वाहन खड़ा करना, किसी चौक पर सवारी उतारने चढ़ाने का कार्य न करना, चौक के पहले या बाद में सवारी को उतारना, तेज एवं लापरवाहीपूर्वक वाहन न चलाने हेतु समझाइश दी गई। साथ ही जो आटो चालक इस मीटिंग में उपस्थित नहीं हुए है उन सभी तक इन सभी बातों को पहुंचाने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त मीटिंग में ऑटो संघ के अध्यक्ष ओमिनिश सिन्हा, उपाध्यक्ष गौरीशंकर महिला ऑटो संघ अध्यक्ष गीता गिल, ई-रिक्शा संघ के अध्यक्ष, ऑटो चालक एवं यातायात पुलिस टीम उपस्थित रहे।

हवाई सेवा का रास्ता साफ,मां महामाया एयरपोर्ट अम्बिकापुर को मिला लाइसेंस

- संवाददाता -
अंबिकापुर, 15 मार्च 2024 (घटती-घटना)।

सरगुजावासियों की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी हो गई है। सरगुजा से हवाई सफर का रास्ता अब साफ हो गया है। भारत सरकार के डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन कार्यालय द्वारा मां महामाया एयरपोर्ट अम्बिकापुर को उड़ान हेतु शुक्रवार को लाइसेंस जारी कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि जिले में लगातार डीजीसीए की टीम द्वारा एयरपोर्ट अधोसंरचना और आवश्यक मानदंडों का निरीक्षण किया जा रहा था। इसी कड़ी में गत दिवस बीसीएएस (ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी) की टीम द्वारा अंतिम निरीक्षण किया गया था।

यात्रियों और उड़ान संचालन की सुरक्षा के लिए विकसित बुनियादी ढांचे की स्थिति और सुविधाओं के लिए बीसीएएस द्वारा निरीक्षण किया गया था। जिसमें सुरक्षित उड़ान संचालन के लिए हवाई अड्डे की उपयुक्तता की पुष्टि की गई जहां टीम ने सभी पहलुओं पर संतोष जताया। अनंतिम मंजूरी जारी करने के लिए रिपोर्ट बीसीएएस मुख्यालय दिल्ली को भेजी गई जिसके परिणाम स्वरूप अगले ही दिन शुक्रवार को डीजीसीए से एयरोड्रम लाइसेंस जारी कर दिया गया है। अब जल्द ही मां महामाया एयरपोर्ट अम्बिकापुर से हवाई सेवा शुरू हो जाएगी।

लुण्ड्रा विधानसभा क्षेत्र में भूमिपूजन कार्यक्रम

- संवाददाता -
लुण्ड्रा, 15 मार्च 2024 (घटती-घटना)।

बेलदगी से मुड़ापारा रोड, रामनगर से लुकुम घुटरा रोड, भकुरा से मेन रोड तक, अजीरमा कला से मांझा बेवरा रोड, डकई से डकई बेवरा रोड, बांसा से कोरवा पारा रोड, सखौली से बांधपारा रोड, चंगोरी रोड, चिरगा बहेरापारा से कोरवा पारा रोड, मेन रोड महोरा से धमना पारा रोड, कोरन्धा से परसा पारा रोड का भूमिपूजन किया जिसमें लुण्ड्रा मण्डल अध्यक्ष महेन्द्र सिंह , धौरपुर अध्यक्ष वैभव सिंह, पदाधिकारी सतीश जैसवाल, देवनारायण यादव, सुनील यादव, दिलेश्वर पैंकरा, सुनील तिवारी, रूपेश गुप्ता एवं भारी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित रहे , आने वाले समय में और भी सभी सड़कों की स्वीकृति एवं कार्य पूर्ण कराने की बात को कहा गया।

पाक सरकार की पहुंच फोन इंटरसेप्शन सिस्टम तक, कोर्ट में बड़े अफसर ने किया खुलासा

इस्लामाबाद,15 मार्च 2024। पाकिस्तान के शीर्ष दूरसंचार निकाय के अध्यक्ष ने एक अदालत को बताया कि दूरसंचार प्राधिकरण ने कानूनी फोन इंटरसेप्शन के लिए एक प्रणाली स्थापित की है। यह प्रणाली सरकार और उसकी एजेंसियों के अधीन है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अदालत में पाकिस्तान के पूर्व मुख्य न्यायाधीश साकिब निसार के बेटे मियां नजम-उस-साकिब और जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी की ऑडियो बातचीत लीक होने की याचिका पर सुनवाई हो रही थी। पाकिस्तान के डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान दूरसंचार प्राधिकरण (पीटीए) के अध्यक्ष मेजर-जनरल हफीजुर रहमान ने गुरुवार को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में एक मामले की सुनवाई के दौरान यह बयान दिया।

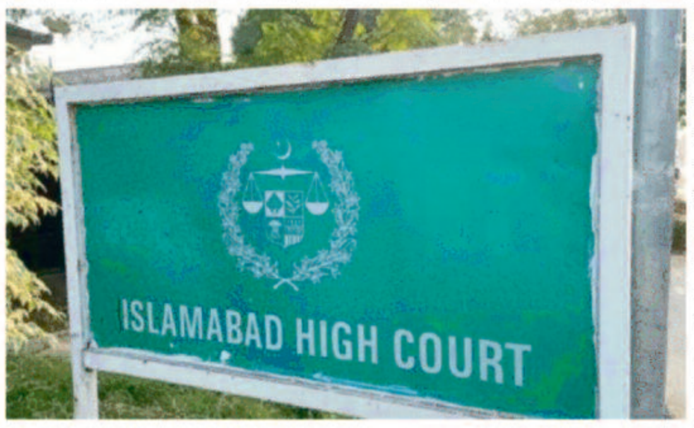

मेजर जनरल हफीजुर रहमान से सवाल आईएचसी पीठ का नेतृत्व कर रहे न्यायमूर्ति बाबर सत्तार ने मेजर-जनरल हफीजुर रहमान से सवाल किया था कि क्या कानूनी फोन इंटरसेप्शन के लिए कोई तंत्र है? इसके जवाब में रहमान ने कहा कि शीर्ष दूरसंचार निकाय ने एक प्रणाली स्थापित की थी, लेकिन यह संघीय सरकार और उसकी एजेंसियों के पास थी। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक रहमान ने कहा कि कानूनी इंटरसेप्शन के प्रावधान को छोड़कर, दूरसंचार ऑपरेटरों के लिए लाइसेंस के सभी प्रावधानों को लागू किया गया है।

क्या अवैध रूप से हो रही है फोन टैपिंग?

अदालत ने पूछा कि क्या ऑडियो रिकॉर्डिंग या फोन टैपिंग अवैध रूप से की जा रही है? इसके जवाब में दूरसंचार प्राधिकरण के वकील ने कहा कि कानूनी फोन इंटरेप्शन सेलुलर सेवाओं से संबंधित नहीं है क्योंकि यह पीटीए, सरकार और संबंधित एजेंसियों का डोमेन है। अदालत ने यह भी पूछा कि क्या टेलीकॉम ऑपरेटर सरकार की अनुमति के बिना किसी व्यक्ति की निजी जानकारी किसी एजेंसी के साथ साझा कर सकते हैं? इसके जवाब में पीटीए के वकील इरफान कादिर ने अदालत को बताया कि गोपनीयता के उल्लंघन के लिए नियामक द्वारा ऐसी सेलुलर कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। अदालत ने पाकिस्तान दूरसंचार प्राधिकरण को दूरसंचार ऑपरेटरों को अगली सुनवाई की तारीख तक एक विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया।

ब्रिटेन में दो मई को आम चुनाव की संभावनाएं नहीं,भारतवंशी पीएम सुनक ने अटकलों पर लगाया विराम

लंदन, 15 मार्च 2024। ब्रिटेन के पहले भारतवंशी प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने तय समय से पहले चुनाव कराए जाने की अटकलों पर विराम लगा दिया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि दो मई को देश के आम चुनाव नहीं कराए जाएंगे। सुनक के बयान के बाद लेबर पार्टी की तरफ से शुरू हुई कयासबाजी खत्म होने की उम्मीद है। लेबर पार्टी ने कहा था कि लंदन में स्थानीय और प्रशासकों के चुनाव के साथ ही आम चुनाव भी कराए जा सकते हैं। खबरों के मुताबिक सुनक ने इस साल की शुरुआत में साल की दूसरी छमाही में चुनाव कराने पर विचार करने की बात कह चुके हैं। हालांकि, हाल के कुछ हफ्तों में मई की शुरुआत में अचानक चुनाव कराए जाने की अटकलें लगाई जाने लगीं।

क्या स्थानीय चुनाव के साथ आम चुनाव की संभावना?

गुरुवार को एक चैनल के साथ इंटरव्यू के दौरान 43 वर्षीय सुनक ने कहा कि लोगों को अनुमान लगाते रहना पसंद है, लेकिन ब्रिटेन में दो मई को आम चुनाव की कोई संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि कई हफ्तों में ब्रिटेन में पुलिस और अपराध आयुक्तों, स्थानीय परिषदों, महापौरों के लिए चुनाव कराए जाएंगे। यह पूछे जाने पर कि क्या उसी समय ब्रिटेन का आम चुनाव भी होगा? सुनक ने कहा, उस दिन आम चुनाव नहीं होगा, लेकिन जब भी आम चुनाव होगा, विकल्प मायने रखेगा।

अमेरिकी सदन के शीर्ष डेमोक्रेट ने यूक्रेन को सहायता संबंधी विधेयक पारित करने का आग्रह किया

वाशिंगटन,15 मार्च 2024। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में शीर्ष डेमोक्रेटिक विधायक ने चैंबर के जीओपी सदस्यों से आग्रह किया है कि वे अगले सप्ताह के अंत तक यूक्रेन के लिए फंडिंग वाले एक विदेशी सहायता पैकेज को पारित करें और इसे हस्ताक्षर के लिए राष्ट्रपति जो बाईडेन के पास भेजें।

सदन में विपक्ष के नेता हकीम जेफ्रीज़ ने बुधवार को कैपिटल हिल में एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा, समय बीतता जा रहा है, और हमें अगले शुक्रवार यानी 22 मार्च से पहले दोनों दलों की सहमति वाले राष्ट्रीय सुरक्षा विधेयक को अंजाम तक पहुँचाना होगा। न्यूयॉर्क डेमोक्रेट ने कहा, ऐसा न करना लापरवाही है। प्रतिनिधि सभा में बहुमत वाले दल के नेता लुइसियाना के रिपब्लिकन सांसद माइक जॉनसन यूक्रेन को अधिक सहायता का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन वह 95 अरब डॉलर के विदेशी सहायता पैकेज पर वोट को रोक रहे हैं ङ्क जिसमें से लगभग 60 अलब डॉलर यूक्रेन को दिए जाएंगे इस विधेयक को हाल ही में सिनेट से मंजूरी मिल चुकी है।

चीन की चांद पर पहुंचने की उम्मीदों को लगा झटका,कामयाब नहीं हो पाया ये मिशन

बीजिंग, 15 मार्च 2024। चीन द्वारा चंद्रमा पर भेजी गई उपग्रहों की जोड़ी अपनी निर्धारित कक्षा तक पहुंचने में कामयाब नहीं हो पाई। चंद्रमा पर पहुंचने की चीन की उम्मीदों के लिए ये एक बड़ा झटका है। बता दें कि कि बुद्धवार शाम को जिचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से डीआरओ-ए और डीआरओ-बी नाम के उपग्रहों को चंद्रमा पर भेजा गया था। लॉन्च होने के बाद पहला और दूसरा चरण सामान्य रूप से संचालित हुआ। इसके बाद के चरण में उड़ान के दौरान दोनों ही उपग्रहों से नियंत्रण छूटने लगा। इस वजह से दोनों उपग्रह पूर्व निर्धारित कक्षा में सही तरीके से प्रवेश करने में विफल रहे। चीन की समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने बताया है कि इसकी वजहों को तलाशा जा रहा है।

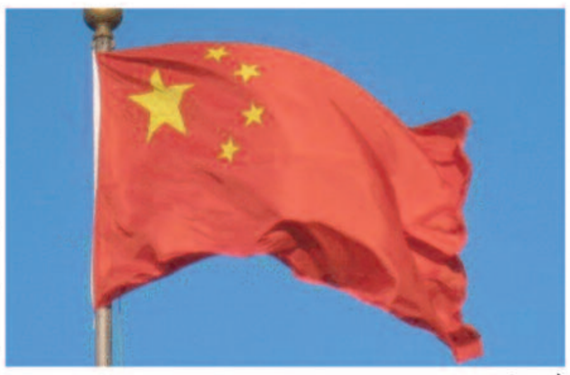

क्या थी चीन की योजना?

हांगकांग स्थित साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने बताया कि चीन के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की योजना थी कि इन दोनों उपग्रहों को चंद्रमा की प्रतिगामी कक्षा (डीआरओ) में प्रवेश कराया जाए। वहां से दोनों साथ में उड़ान भरते और तीसरे उपग्रह डीआरओ-एल के साथ काम करते। डीआरओ-एल को फरवरी महीने में पृथ्वी और चंद्रमा के बीच लेजर-आधारित नेविगेशन प्रौद्योगिकियों का परीक्षण करने के लिए जिलॉन्ग 3 रॉकेट द्वारा पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया था। डीआरओ चंद्रमा की सतह से हजारों किलोमीटर ऊंचाई पर है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह अत्यधिक स्थिर है, जो अंतरिक्ष यान को ईंधन का उपयोग किए बिना लंबे समय तक ट्रैक पर रहने की अनुमति देता है। चीनी वैज्ञानिकों की मानें तो अनुसंधान और अन्वेषण के लिए यह काफी फायदेमंद हो सकता ।

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में प्रवेश हेतु 18 अप्रैल तक

– संवाददाता –
अंबिकापुर, 15 मार्च 2024 (घटती-घटना)।

जिला स्तरीय छत्तीसगढ़ आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति के सहायक आयुक्त एवं सचिव ने बताया कि भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय नई दिल्ली अंतर्गत गठित राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति नई दिल्ली द्वारा प्रवर्तित एवं छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में शिक्षण सत्र 2023-24 में कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु ऑनलाईन आवेदन फार्म विभागीय वेबसाईट http://eklavya.cg.nic.in पद पर भरा जायेगा। उन्होंने बताया कि वेबसाईट में ऑनलाईन आवेदन 18 मार्च से 18 अप्रैल 2024 तक भरा जा सकता है। ऑनलाईन भरे गये फार्म में त्रुटि सुधार की तिथि 19 से 26 अप्रैल निर्धारित है। प्रवेश परीक्षा 18 मई को आयोजित की जाएगी।

प्रवेश हेतु पात्रता-उन्होंने बताया कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में प्रवेश हेतु पात्रता में विद्यार्थी की आयु 31 मार्च या 01 अप्रैल 2024 को 10 से 13 वर्ष के मध्य हो (दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए आयु सीमा में अधिकतम 02 वर्ष की छुट रहेगी), प्रवेश के समय कक्षा 5वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी हो, छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा घोषित जनजातीय वर्ग या समुदाय का सदस्य हो, विद्यार्थी को किसी अन्य विद्यालय से निष्काषित न किया गया हो।

अदाणी फाउंडेशन के महिला दिवस समारोह में 300 से अधिक महिलाएं हुई शामिल

– संवाददाता –
अंबिकापुर,15 मार्च 2024 (घटती-घटना)।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अदाणी फाउंडेशन ने मंगलवार को 10 ग्रामों की 300 से अधिक महिलाओं के साथ मिलकर सशक्तिकरण सम्मेलन का आयोजन किया। जिले के उदयपुर ब्लॉक में स्थित अदाणी कौशल विकास केंद्र ,ग्राम साल्ही के सभा भवन में आयोजित इस सम्मेलन में ग्राम स्तर में मुख्य रूप से उत्कृष्ठ कार्य करने वाली, आसपास के गांव परसा, घाटबर्रा, बासेन, हरिहरपुर इत्यादि ग्रामों की महिलाएं शामिल हुई। सम्मेलन के आयोजन का मुख्य उद्देश्य समाज एवं ग्रामीण स्तर पर अपने कार्यो द्वारा अपनी पहचान बना रही महिलाओं का सम्मान करना था।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अदाणी इन्टरप्राइजेज लिमिटेड के श्री राम द्विवेदी क्लस्टर प्रमुख- मानव संसाधन विभाग थे जबकि अध्यक्षता श्री अमित तिवारी, क्लस्टर प्रमुख- वित्त और श्री आरएस दुबे, सुरक्षा प्रमुख ने की। विशिष्ट अतिथियों में श्रीमती भोजवंती पैकरा जनपद अध्यक्ष, उदयपुर, श्रीमती रमुनिया करियाम बीडीसी सदस्य, चकेरी, श्रीमती मंजूमति करियाम सरपंच, शिवनगर गांव, श्रीमती मीना उर्रे सरपंच, जनार्दनपुर गांव, शिवकुमार उपसरपंच, शिवनगर, श्रीमती कल्पना भदौरिया सरदा महिला मंडल अध्यक्ष, सुश्री निशा श्रीवास्तव महिला एवं बाल विकास पर्यवेक्षिका और देव सिंह करियाम घाटबर्रा प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक शामिल थे। इसके अलावा अदाणी इन्टरप्राइसेस लिमिटेड भूमि विभाग प्रमुख श्री राजेश सॉव, सहित अदाणी विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य दिलीप पाण्डेय, राकेश परमार, सहित अन्य गणमान्य अतिथियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज की।

कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों के स्वागत और दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस दौरान दिव्यदीप हायर सेकेंडरी स्कूल, शिवनगर के छात्रों एवं महिलाओं द्वारा मनमोहक नृत्य सहित अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किये गये। कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रमुख अतिथियों द्वारा महिला सशक्तीकरण के महत्व और समाज में महिलाओं के योगदान को रेखांकित करते हुए प्रेरणादायक भाषण दिए गए। इसके अलावा, महिला सशक्तीकरण के विषय पर आधारित एक प्रेरणादायक वीडियो भी प्रस्तुत किया गया, जिसने कार्यक्रम में उपस्थित सभी महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के समापन में अदाणी फाउंडेशन की ओर से महिला कर्मचारियों को उनकी निष्ठा और कठिन परिश्रम के सम्मान में उपहार भेंट किए गए। कार्यक्रम में न केवल महिला दिवस की भावना का सम्मान किया, बल्कि लैंगिक समानता और महिला अधिकारों के लिए किए जा रहे निरंतर प्रयासों को भी उजागर किया। सरगुजा क्षेत्र की महिलाओं ने महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए अदाणी फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस सार्थक कार्यक्रम की सराहना की।

पिता के आकस्मिक निधन पर पुत्र को मिली अनुकम्पा नियुक्ति

– संवाददाता –
अंबिकापुर, 15 मार्च 2024 (घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सेवाकाल के दौरान शासकीय सेवक की मृत्यु होने पर उसके आश्रित परिवार के सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति देने के सम्बंध में एकजाई पुनरीक्षित निर्देश 2013 जारी किया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला कार्यालय अम्बिकापुर में भृत्य धनसाय का आकस्मिक निधन 21 फरवरी 2023 को हो गया था। कलेक्टर विलास भोस्कर द्वारा शुक्रवार को कलेक्टर कक्ष में दिवंगत धनसाय के पुत्र सामुअल लकड़ा को अनुकम्पा नियुक्ति आदेश प्रदान कर आगे भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं। इसी प्रकार उन्होंने दिवंगत धनसाय की पत्नी श्रीमती रमझो को पेंशन अदायगी आदेश भी प्रदान क़िया। अनुकम्पा नियुक्ति आदेश एवं पेंशन अदायगी आदेश को साथ ही प्राप्त कर परिवारजनों के चेहरे पर राहतभरी मुस्कान आ गई है, उन्होंने इस हेतु राज्य शासन और प्रशासन का धन्यवाद किया। अनुकंपा नियुक्ति आदेश में कहा गया है कि उनकी नियुक्ति तीन वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी।

माइनर नहर पे कब्जा

– संवाददाता –
अंबिकापुर, 15 मार्च 2024 (घटती-घटना)।

अंबिकापुर शहर से लगे बांकी डेम से निकलने वाली सोहगा माइनर नहर को बंद कर भू-माफिया ने उस पर कब्जा कर बिल्डिंग बना दिया। यही नहीं, अतिक्रमणकारी नहर की जमीन को प्लाटिंग कर गलत तरीके से बेच रहे हैं। इससे 15 गांव के लोगों को जहां पानी नहीं मिल रहा, वहीं दस करोड़ की लागत से इस डैम की बंद पड़ी सिंचाई परियोजना में अतिक्रमण रोड़ा बन रहा हैं । आपको बता दे पूर्ववर्ती सरकार के मुख्यमंत्री से शिकायत भी की गई थी। सीएम ने कार्रवाई के निर्देश दिए थे, लेकिन अब तक अतिक्रमण नहीं हटा। इससे गांवों में आक्रोश है। क्षेत्र के ग्रामीणों ने एक बार फिर कलेक्टर से मुलाकात कर अतिक्रमण हटाने की मांग की हैं ग्रामीणों ने बताया कि बांकी डेम से कांतिप्रकाशपुर, खैरबार, लोंगापानी सहित पंद्रह से अधिक गांवों में सिंचाई के लिए पानी पहुंचाने माइनर नहर बीस साल पहले बनाई गई थी। इसके बनने के बाद सात सालों तक लोगों को पानी भी मिला। लेकिन अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र में पानी सप्लाई करने से कुछ सालो बाद बांकी डैम में पानी कम होने लगा तो कई गांवों में पानी देना बंद कर दिया गया। इसी का फायदा उठा कर अतिक्रमणकारी और भूमाफिया सक्रिय हो गए, लोकेशन अच्छा होने और कई सालों से सूखी नहर को देखकर लोगों ने धीरे-धीरे नहर में मिट्टी डालकर भरना शुरू कर दिया और बाद में उससे कब्जा कर मकान बना लिए। इससे पूरी नहर बंद हो गई। आलम यह है नहर सिर्फ कागजों में रह गई है धरातल पर वह नजर नहीं आता यदि उसे देखने जाएं तो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकेगा कि वहां नहर थी या नहीं.. वहीं विभाग भी नहर को बचाने में अपनी सक्रिय भूमिका नहीं दिखा रही है।

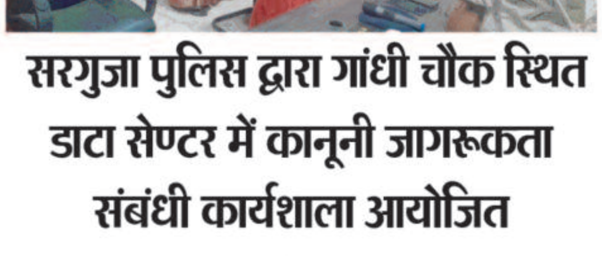

सरगुजा पुलिस द्वारा गांधी चौक स्थित डाटा सेण्टर में कानूनी जागरूकता संबंधी कार्यशाला आयोजित

– संवाददाता –
अंबिकापुर, 15 मार्च 2024 (घटती-घटना)।

» महिलाओ से संबंधित लैंगिक शोषण, घरेलू हिंसा,साइबर अपराध एवं महिलाओं के विरूद्ध घटित अपराधों से संबंधित कानूनी प्रावधानों की दी गई विस्तृत जानकारी

» एनयुएलएम की महिलाओ से रूबरू होकर सुनी गयी उनकी समस्याएं...

सरगुजा पुलिस के द्वारा महिला सुरक्षा एवं जागरूकता हेतु जारी ÷÷विश्वास अभियान÷÷के तहत महिलाओं को लैंगिक शोषण, घरेलू हिंसा, साइबर अपराध एवं महिलाओं के विरूद्ध घटित अपराधों से संबंधित कानूनी प्रावधानों से अवगत कराने हेतु सरगुजा पुलिस के द्वारा अम्बिकापुर गांधी चौक स्थित डाटा सेण्टर में जाकर एनयुएलएम की महिलाओं से रूबरू होकर समस्याऐं सुनी गई। उन्हें जागरूक करने हेतु महिला संबंधी अपराधों तथा बचाव संबंधी आवश्यक जानकारी दी गई। कार्यशाला में उपस्थित एनयुएलएम अधिकारीगण एवं एनयुएलएम की महिलाओं को छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा जारी महिला सुरक्षा संबंधी अभिव्यक्ति एप्प डाउनलोड कराकर उपयोग संबंधी जरूरी जानकारियां दी गई।

कार्यशाला के दौरान एनयुएलएम प्रबंधक सौरव सिंह, एमएसएसव्हीपी संचालिका, एसएण्डएलआरएम समूह सदस्य, सरगुजा पुलिस महिला सेल, गूंज टीम मौजूद रहे।

कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने प्रेस वार्ता कर गिनाई विष्णु देव सरकार की उपलब्धियां

» तीन माह में मोदी की गारंटी व विष्णु देव के सुशासन का असर धरातल पर दिख रहा...

» महतारी वंदन योजना से महिलाओं को सम्मान व हक मिला...

– संवाददाता –
सूरजपुर,15 मार्च 2024 (घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के तीन माह पूरे होने पर जिला भाजपा द्वारा प्रेस वार्ता कर सरकार की उपलब्धियां गिनाई।प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में हमारी सरकार ने 13 दिसंबर 2023 को शपथ ली थी और आज हमारी सरकार को तीन माह पूरे हो चुके है।

देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जो गारंटियां दी थी, तीन महीने के इस अल्प समय में ही हमारी सरकार ने उन्हें पूरा करने अपनी प्रतिबद्धता दिखायी है। हमारी सरकार ने गरीब, किसान, महिलाओं और युवाओं के हित में बड़े फैसले लिए है। सरकार ने पहली केबिनेट में ही छत्तीसगढ़ के 18 लाख आवासहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराने का अभूतपूर्व निर्णय लिया। इसके लिए वर्ष 2023-24 के अनुपूरक बजट में 3,799 करोड़ रूपए और वर्ष 2024-25 के बजट में 8,369 करोड़ रूपए, इस प्रकार कुल 12,168 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

अन्नदाताओं से हमने वादा किया था कि उन्हें दो वर्षों के धान खरीदी के बकाया बोनस की राशि का भुगतान करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी के जन्मदिन सुशासन दिवस के अवसर पर 3716 करोड़ रूपए किसानों को दिया है।

हमारी सरकार ने प्रदेश की विवाहित महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन और सशक्तिकरण के लिए प्रतिमाह 1000 रूपए देने का वादा हमने किया था। मोदी की इस गारंटी को पूरा करते हुए हमने प्रदेश में 'महतारी वंदन योजना' लागू कर दी है। इसके अंतर्गत 70 लाख से अधिक महिलाओं को 10 मार्च को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की वर्चुअल उपस्थिति में लगभग 655 करोड़ रूपए सीधे उनके खातों में अंतरित कर दी गई है।

क्या कभी बुझेगी चिरमिरी के जमीन के नीचे की आग ?

दहक रही जमीन के निचे आग और जहरीले धुएं के बीच जी रहे लोग

-रवि सिंह-
एमसीबी, 15 मार्च 2024
(घटती-घटना)।

एमसीबी जिले के एसईसीएल चिरमिरी क्षेत्र में जमीन के नीचे कई सालो से आग दहक रही है। जमीन के नीचे कोयले में सुलग रही आग को बुझाने को लेकर एसईसीएल प्रबंधन खास गंभीरता नहीं दिखा रहा है। खदानों में आग से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम होते हैं, मगर चिरमिरी में लगी आग को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। अब तक इसे बुझाने में दिखाई गई लापरवाही का ही नतीजा है यह आग अब बेकाबू होने की स्थिति में है। इससे खनिज संपदा को तो नुकसान हो ही रहा है साथ ही आम लोगों को भी जहरीले धुएं के बीच जीना पड़ रहा है।

आपको बता दें कि चिरमिरी क्षेत्र में कोयले का काफी अधिक भंडार है। यहां कोयले की खुली और भूमिगत खदानें हैं। जिन पुराने भूमिगत खदानों को आग की वजह से बंद किया गया, वहां बरसों से जमीन के नीचे आग दहक रही है। चिरमिरीवासी जहरीले धुंए में जीवन व्यतीत करने को बाध्य हैं। फायर प्रोजेक्ट एरिया में आग को बुझाने के बजाए, जलते हुए कोयले का ही ट्रांसपोटेशन किया जा रहा है। कालीबाड़ी के पास कुरासिया के बंद खदान में आग लगने के कारण 2004 में एसईसीएल ने खदान के मुहाने पर दीवार जोड़कर खदान को बंद कर दिया था, लेकिन अंदर लगी आग को नहीं बुझाया गया। यही हाल अन्य खदानों का है। आपको बता दें कि कोयला निकालने के बाद एसईसीएल को खदानों में रेत फीलिंग कर खदान को बंद करना होता है, लेकिन एसईसीएल अफसरों की लापरवाही ने चिरमिरीवासियों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया है।

गैस इंसानों के साथ जानवरों के लिए भी खतरनाक

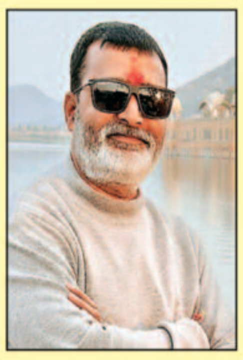

भाजपा नेता संजय सिंह ने कहा कि चिरमिरी क्षेत्र में ही मेरा जन्म हुआ है। शहर में जिधर भी जाएंगे जहरीली गैस निकलती नजर आती है। पहले जानवरों की मौत हो चुकी है। यह गैस इंसानों के साथ जानवरों के लिए भी खतरनाक है। एसईसीएल कोयले का दोहन करती आई है,अंडर ग्राउंड खदान से कोयला निकालने के बाद रेत फीलिंग किया जाता है, लेकिन यहां ऐसा नहीं होता है, जिस कारण खदानों में आग भड़क रही है। एसईसीएल गैस वाले स्थानों पर ऊपर से मिट्टी फीलिंग कर दिखावा करती है।

एसईसीएल प्रबंधन पर्यावरण को बर्बाद करने में लगा अमादा

आरटीआई कार्यकर्ता व समाज सेवक राजकुमार मिश्रा ने कहा कि हमारा चिरमिरी शहर आग के ज्वालामुखी के ऊपर बसा हुआ है। यहां कोयला निकालकर चूहे की बिल जैस आकृति छोड़ दी गई है। कोयला ज्वलनशील है इसलिए ऑक्सीजन के संपर्क में आकर आग लग जाती है। जिससे जगह-जगह कार्बन मोनोऑक्साइड निकलने लगता है। पहले कई जीव जंतुओं की मौत हो चुकी है। लेकिन एसईसीएल प्रबंधन पर्यावरण को बर्बाद करने में लगा हुआ है। इस संबंध में मैंने पहले एफआईआर भी की थी।

जहां गरीबों को पक्के आवास देने के दावे वही निगम के सुलभ शौचालय में रहने को मजबूर है क्यों एक परिवार ?

कागज और किस्तों के जाल में अधूरा है गरीब का आशियाना पर जानकारी लेने वाला कोई नहीं

-रवि सिंह-
चिरिमिरी, 15 मार्च 2024
(घटती-घटना)।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जरूरतमंदों को पक्के आवास देने को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं। लेकिन इन दावों के बीच नगर निगम चिरमिरी के वार्ड क्रमांक 2 में एक ऐसा परिवार भी है जो शौचालय में रहने को मजबूर है। सुनने में बेशक यह अटपटा लगे लेकिन यह सच्चाई है। जो आवास योजना के सारे दावों की पोल खोल रहा है।

मामला नगर निगम चिरमिरी के वार्ड क्रमांक 2 में गाड़ा बुडा का है। यहां करीब 15 साल से एक परिवार निगम के बंद पड़े सुलभ शौचालय में निवास कर रहा है। यह इस परिवार का शौक नहीं बल्कि मजबूरी है। वजह है परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाला घर सरकारी नियमों और कागजों की पेच में फंसा हुआ है। परिवार के पास वर्तमान में खुद की जमीन पर एक कच्चा घर है। जिसमें माता-पिता बहन सहित अन्य लोग रहते हैं। क्योंकि कच्चा घर छोटा है और उसके

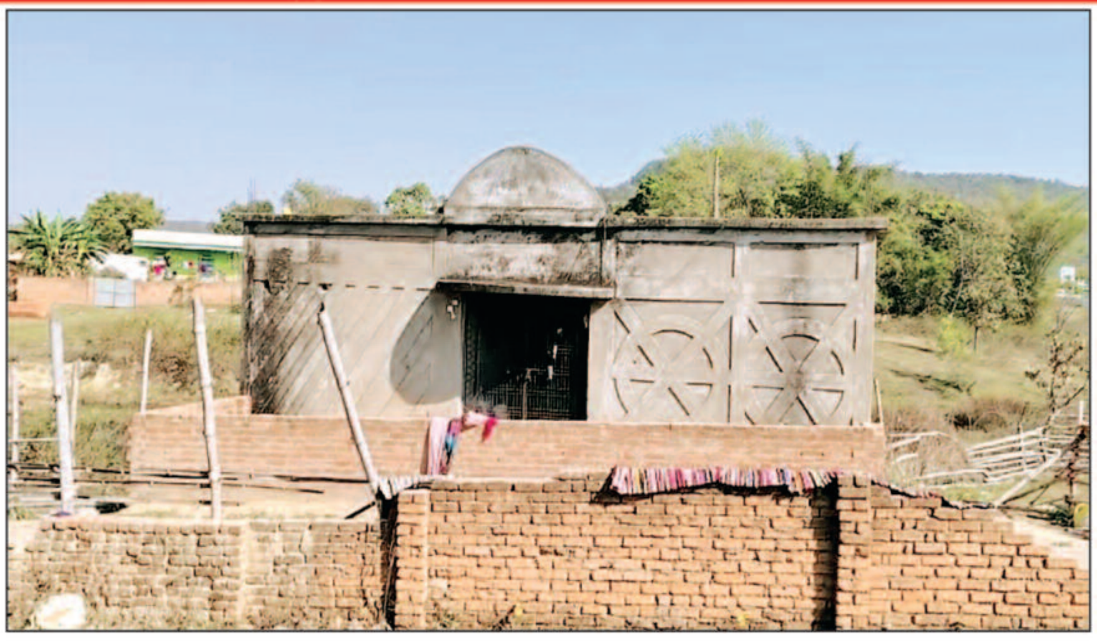

छप्पर में कई जगह दरार है। इस कारण मजबूरी में यह परिवार निगम के बंद पड़े सुलभ शौचालय में निवास करने को मजबूर है। ऐसा नहीं है कि निगम के अधिकारी और आवास योजना के इंजीनियर इस बात से अनजान है। जिस सुलभ शौचालय में यह परिवार निवास कर रहा है वह नगर निगम कार्यालय से करीब डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। आश्रितों का कहना है कि निगम के अधिकारियों और स्थानीय पार्षद को कई बार परेशानी की दुहाई दे चुके हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। 15 साल से शौचालय में निवासरत हैं तो अब निगम से सहायता मिलने की उम्मीद भी नहीं है।

योजना की किस्त पूरी नहीं मिली- ऐसा

नहीं है कि परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास नहीं मिला। आवास तो मिला है पर उसकी छत गायब है। अब परिवार आवास की छत के लिए इंतजार कर रहा है।
दरअसल परिवार को आवास योजना के तहत आवास स्वीकृत होने के बाद एक किस्त जारी की गई थी। परिवार की रैमूनिया बताती है कि एक किस्त मिलने के बाद डोर लेवल तक आवास का निर्माण कराया गया इसमें किस्त कम पड़ने के कारण परिवार ने अपनी जमा पूंजी भी लगा दी। अब दूसरे किस्त के इंतजार के दौरान ही निगम के इंजीनियर ने कहा कि छत ढलाई करो तभी दूसरा किस्त दिया जाएगा। चूंकि परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वह छत ढलाई कर सके इस कारण आवास योजना आज तक अधूरा पड़ा है।
परिवार की अनीता बताती है कि पिछले 15 सालों से वह निगम के शौचालय में ही निवास कर रही हैं। यहां पानी सड़क के दूसरे ओर से बर्तनों और डब्बे में लाया जाता है। वहीं बिजली के लिए अन्य साधनों पर आश्रित है। पिछले 15 सालों में कोई सुध लेने नहीं आया इस कारण अब लोगों को परेशानी बताना भी छोड़ चुकी है।

आवास योजना में ही गड़बड़ी

नगर निगम चिरमिरी क्षेत्र में बनाए गए प्रधानमंत्री आवासों में गड़बड़ी होने की बात सामने आ रही है। यहां कुछ मकान निर्माण अधीन है तो कुछ कागजों पर ही पूरे कर लिए गए हैं। कई मकानों में लाल ईंट का प्रयोग किया गया है। कुछ की किस्त तो कुछ कागजों के पेच में फंसे हुए हैं। शौचालय में आश्रित परिवार का प्रधानमंत्री आवास भी अधूरा पड़ा हुआ है। आवास की खिड़की की ग्रिल और दरवाजे एक ओर रखे हुए हैं। निर्माण के लिए बालू एक और रखी हुई है केवल बीम और कॉलम के सहायता से स्ट्रक्चर को खड़ा कर ईंट की दीवार बनाई गई है। परिवार अब भी छत ढलाई का इंतजार कर रहा है।

परेशानियां किसे सुनाएं

निगम के जिस सुलभ शौचालय में यह परिवार निवास कर रहा है वह करीब 15 साल से बंद पड़ा था। इस शौचालय में प्रवेश करते ही सामने खाना बनाने के लिए मिट्टी का चूल्हा दिखता है। कमरे के एक ओर बच्चों की किताबें तो वहीं दूसरी ओर सोने के लिए बिस्तर लगाया हुआ है। इस परिवार में सदस्यों ने इसे ही अपना आशियाना बनाया हुआ है। यहां ना तो बिजली की उचित व्यवस्था है और ना ही पानी की बावजूद इसके परेशानियों के बीच परिवार यहां बसेरा बनाए हुए हैं। परिवार के सदस्यों का कहना है कि अपनी परेशानियां किसे सुनाए कोई सुनने को नहीं आता।

जन्मदिन पर प्राथमिक व माध्यमिक शाला महगवाँ में किया गया न्योता भोजन का आयोजन

-संवाददाता-
सूरजपुर, 15 मार्च 2024
(घटती-घटना)।

जिला शिक्षा अधिकारी सूरजपुर के मार्गदर्शन में विकासखंड सूरजपुर के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला महगंवा में चंद्रबेस सिसोदिया (जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग सूरजपुर) के पुत्र के जन्मदिन के अवसर पर विद्यालय में न्योता भोजन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से लता बेक (सहायक संचालक) एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारी भानु प्रताप चंद्राकर एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी सुनील कुमार पोर्ते, खंड स्त्रोत समन्वयक मनोज मंडल, रुद्रेश प्रसाद बेसिन, देवेंद्र कुमार साहू , विकास श्रीवास्तव, सूरज सोनी, संदीप बहेरा, अजित गुप्ता तथा डुमरिया संकुल के संकुल समन्वय शिवचंद साहू उपस्थित रहे।

विकासखंड शिक्षा अधिकारी चंद्राकर जी ने जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए न्योता भोजन के बारे में कहा कि छत्तीसगढ़ की स्कूलों में प्रधानमंत्री कौशल शक्ति योजना के अंतर्गत सभी स्कूलों में न्योता भोजन योजना लागू करने का शासन द्वारा निर्णय लिया गया है न्योता भोजन का उद्देश्य समुदाय के बीच अपनेपन की भावना का विकास, भोजन के पोषक मूल्य में वृद्धि तथा सभी समुदाय वर्ग के बच्चों में समानता की भावना विकसित करना है तथा अपने उद्बोधन में जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए इस कार्यक्रम में शामिल होकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की तथा सभी को इस प्रकार के कार्यक्रम करने के लिए आग्रह किया। इस न्योता भोजन कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने अपने हाथों से बच्चों के थाली में फल, पूरी, सब्जी इत्यादि परोस कर स्वयं बच्चों के साथ भोजन किया।

इस कार्यक्रम में नवापारा संकुल समन्वय बालेश्वर प्रसाद साहू, शाला प्रबंधन समिति के सदस्य, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला महगवाँ के प्रधान पाठक मेरी प्रकिस्ता कुजूर, शिक्षिका शशि कला लकड़ा, शिक्षक रवि बाबू कौशिक, शासकीय प्राथमिक शाला महगवाँ से शिक्षिका प्रीति पटेल, एवं हेमलता साहू तथा दोनों विद्यालय के छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व अस्तित्व में नहीं आ सका...कांग्रेस सरकार ने रोक रखा था नोटिफिकेशन...क्या भाजपा सरकार में आ पाएगा अस्तित्व में ?

-रवि सिंह-
कोरिया, 15 मार्च 2024
(घटती-घटना)।

केंद्र सरकार ने 2021 में गुरु घासीदास नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया, लेकिन यह अस्तित्व में नहीं आ सका है। टाइगर रिजर्व का नोटिफिकेशन ढाई साल से प्रदेश की कांग्रेस सरकार रोके हुए थी। शासन का मत था कि जहां रिजर्व घोषित किया गया, उस पूरे इलाके में महत्वपूर्ण खनिजों की खदानें और घना जंगल है। रिजर्व बनने के बाद अगर इस इलाके में खनन बंद करना पड़ा तो इससे राज्य को गंभीर आर्थिक संकट उठाना पड़ सकता है।

आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में पिछले एक साल में टाइगर 19 से घटकर 17 रह गए है। यह रिपोर्ट केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने जारी की है। दूसरी ओर प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व मंजूर हैं, लेकिन अस्तित्व में केवल 3 ही हैं। चौथा यानी गुरु घासीदार टाइगर रिजर्व केंद्र से 2021 में मंजूर जरूर हुआ, लेकिन राज्य शासन ने इसे रोक दिया। पार्क को रिजर्व में बदलने का प्रस्ताव 2012 में तत्कालीन भाजपा सरकार ने केंद्र को भेजा था। इसके शुरू होने से आय के स्त्रोत बाधित होंगे। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रदेश की विष्णु देव आय की सरकार टाइगर रिजर्व को लेकर क्या फैसला लेती है।

भाजपा की सरकार ने भेजा था ड्राफ्ट

छत्तीसगढ़ की पूर्ववर्ती भाजपा सरकार की ओर से गुरु घासीदास नेशनल पार्क और तमोर पिंगला सेंचुरी को मिलाकर टाइगर रिजर्व बनाने का ड्राफ्ट एनटीसीए को भेजा गया था। एनटीसीए ने ही इसे टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी दी, लेकिन कांग्रेस शासन में यह मामला इस रिजर्व एरिया के कोल ब्लॉक, आइल ब्लॉक और मिथेन गैस ब्लॉक पर फंस गया है। इसी संबंध में राज्य खनिज विभाग और केंद्र को पत्र लिखाकर अभिमत मांगा गया, हालांकि अंतिम निर्णय राज्य का ही है। प्रस्तावित गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व क्षेत्रफल के हिसाब से देश का तीसरा सबसे बड़ा रिजर्व होगा। गुरुघासीदास पार्क के डायरेक्टर ने कहा कि प्रस्तावित टाइगर रिजर्व को लेकर राज्य स्तर पर प्रक्रिया चल रही है।

बाघ की सुरक्षा के लिए बेहतर-

जब एनटीसीए ने मंजूरी दे दी है, तो उसके बाद कोई सवाल ही नहीं बचता है। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व में टाइगर हैं और इनका अच्छा मूवमेंट भी है। निश्चित तौर पर टाइगर रिजर्व के नोटिफिकेशन के बाद यह एनटीसीए के अधीन आ जाएगा। टाइगर की सघन निगरानी शुरू हो जाएगी, प्रोटेक्शन और ज्यादा होगा। साथ ही बायोडायर्सिटी के लिहाज से महत्वपूर्ण होगा।

प्रोत्साहन राशि में करोड़ों रुपए के फर्जीवाड़े की जांच तात्कालिक कांग्रेस सरकार में जांच के नाम पर महज खानापूर्ति कर जांच को कर दिया गया रफा-दफा...

क्या वर्तमान की भाजपा की सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खड़गवां में हुए करोड़ों रुपए के प्रोत्साहन राशि में भ्रष्टाचार की जांच कराकर इस कारनामे की खुलासा करेगी ?

-राजेन्द्र शर्मा-
खड़गवां, 15 मार्च 2024
(घटती-घटना)।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खड़गवां में प्रोत्साहन राशि में हुए करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में पदस्थ नेत्र सहायक जिनके द्वारा प्रोत्साहन राशि के प्रकरण तैयार कर पोर्टल पर डाले जाते थे वो भी संदेह में है क्या इन पर कार्यवाही होगी या इन्हें ऐसे ही जीवन दान प्रदान किया जाएगा ?

प्रोत्साहन राशि में हुए फर्जी वाड़े की जांच को आच नहीं आई है आच भी क्यों आये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खड़गवां में पदस्थ नेत्र सहायक चिकित्सक के द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रोत्साहन राशि के प्रकरण बनाने का कार्य किया जाता हो और उसका नजदीकी रिश्तेदार तात्कालिक कांग्रेस सरकार के विधायक का नजदीकी हो तो हुए भ्रष्टाचार कि जांच की जिस चूल्हे में पका रही थी उस चूल्हे को ही बुझा दिया गया क्योंकि इसके लिए एक कहावत बहुत मशहूर है कि **सईयां भय कोतवाल तो अब डर काहे** का इस तर्ज में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खड़गवां में करोड़ों रुपए की प्रोत्साहन राशि में खुलेआम भ्रष्टाचार किया गया है। प्रोत्साहन राशि में करोड़ों रुपए के हुए भ्रष्टाचार की जांच अब भी अधूरी है, हालांकि जांच के नाम पर

खाना पूर्ती करते हुए एचआरएमआईएस पोर्टल में वास्तविक पदनाम से भिन्न पद नाम कर प्रोत्साहन राशि का लाभ दिया गया था। इस करोड़ों रुपए की प्रोत्साहन राशि में हुए भ्रष्टाचार में कांग्रेस के तात्कालिक नेताओं का राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होने के कारण जांच में आए अधिकारियों पर भी बड़ा दबाव देकर जांच को कई तरह से प्रभावित किया गया है। इधर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खड़गवां में पदस्थ अधिकारी का कहना है कि प्रोत्साहन राशि में किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं किया गया है। तो इस प्रोत्साहन राशि जांच मामले को निष्पक्ष जांच होने देना चाहिए जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।

पुनः की गई कार्यवाही की मांग

इस करोड़ों रुपए के प्रोत्साहन राशि के मामले में वर्तमान सरकार से पुनः शिकायत की गई है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खड़गवां में हुए करोड़ों रुपए की प्रोत्साहन राशि में भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच की मांग कर भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी कर्मचारीओ पर सख्त कार्यवाही करने की मांग भाजपा सरकार से की है? प्रोत्साहन राशि में हुए फर्जी वाडे की पूर्व सरकार ने जांच महज खानापूर्ति के लिए कराई गई जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खडगवां के कुछ कर्मचारीयों से जांच के नाम पर थोड़ी बहुत वसूली की कार्यवाही कर जांच के नाम पर खानापूर्ति कर इस मुद्दे पर मिट्टी डालकर दफ़न करना चाहती थी मगर यह प्रोत्साहन राशि का मामला हमेशा कही ना कही चर्चा का विषय बना हुआ है, दरअसल यह घोटाला प्रदेश स्तर का होने के कारण बडा सुर्खियों में रहा है आज भी है मगर तात्कालिक कांग्रेस सरकार की राजनीतिक संरक्षण का शिकार हो कर रह गया। इस करोड़ों रुपए की प्रोत्साहन राशि मामले में राज्य स्तरीय निष्पक्ष जांच होतो राज्य के ज्यादातर स्वास्थ्य केद्रों में जांच उपरांत करोड़ों रुपए के घोटाले सामने आ सकते हैं।

जांच के नाम पर की गई खानापूर्ति

पूर्व में उक्त प्रकरण समाचार पत्रों में प्रकाशित होने के बाद तात्कालिक कांग्रेस सरकार ने जांच के नाम पर चार सदस्सदस्यीय जांच समिति का गठन 11/1/23 को किया गया , जिस जांच समिति के द्वारा 13/1/23 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खड़गवां का भ्रमण कर जांच की गई जांच तो महज एक खानापूर्ति ही थी जांच में आए अधिकारियों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खड़गवां के बीएमओ एवं अन्य अधिकारीयों के द्वारा ए सी कमरे में बैठाकर उनकी इतना सेवा सत्कार किया गया और चार सदस्यीय जांच टीम वहीं एसी कमरे में बैठकर ही प्रोत्साहन राशि में हुए करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार की शिकायत जांच पूरी कर जांच के नाम पर खानापूर्ति कर दिया गया था। इस करोड़ों रुपए के प्रोत्साहन राशि में हुए भ्रष्टाचार की गूंज तात्कालिक कांग्रेस सरकार में राज्य स्तर तक होने के बाद भी तात्कालिक कांग्रेस सरकार ने मामले को बड़ी ही सहजता से जमींदोज कर दिया गया क्या वर्तमान भाजपा की सरकार के द्वारा इस करोड़ों रुपए की प्रोत्साहन राशि में हुए भ्रष्टाचार की जांच कराकर दूध का दूध और पानी का पानी करेगी ?

23 करोड़ के व्यय के साथ 22 लाख रूपए आय का बजट प्रस्तुत

-संवाददाता-
सूरजपुर, 15 मार्च 2024
(घटती-घटना)।

नगर पालिका अध्यक्ष केके अग्रवाल ने नपा की सामान्य सभा की बैठक में गत वर्ष के आय-व्यय का लेखा प्रस्तुत कर नए सत्र 2024-25 का बजट प्रस्तुत किया। जिसमें 23 करोड़ 93 लाख रूपए आय तथा 23 करोड़ 71 लाख रूपए के व्यय के बीच 22 लाख रूपए लाभ का बजट नपा में प्रस्तुत किया गया। परिषद की बैठक में उपाध्यक्ष सहित समस्त पार्षदों ने करतल ध्वनि से बजट को पारित किए। इस दौरान नपा अध्यक्ष श्री अग्रवाल ने बताया कि नपा ने बीते चार वर्षों में किसी प्रकार का कोई नया कर नहीं लगाया और न ही आगे कोई नया कर लगाया जायेगा। गत तीन वर्षो से नपा लाभ का बजट प्रस्तुत कर रही है और बीते बजट के अनुरूप सभी प्रावधानों पर नगर पालिका ने सफलता प्राप्त की है। नगर में सुविधा विस्तार के साथ पिछले बजट के अधिकांश कार्यो को पूर्ण करने के साथ अधोसंरचना विकास में नपा ने नगर के समस्त वार्डो में सड़क, नाली, भवन व चारदीवारी निर्माण सहित निर्माण कार्यों में इतिहास रचा है। इसके साथ ही विद्युत, पेयजल, स्वच्छता सहित मूलभूत सुविधाओं में लगातार इजाफा होने के साथ स्वच्छ भारत अभियान में निकाय को मिली स्टार रैंकिंग और दिल्ली में सम्मान मिलने पर नपा अध्यक्ष ने जनप्रतिनिधियों व निकाय के अधिकारी-कर्मचारियों को बधाई दी है। उन्होंने नपा की राजस्व आय बढ़ाने के लिए हुए क्रांतिकारी कार्यों के लिए पूरी टीम को बधाई देते हुए नए सत्र के प्रस्तावित बजट में 39 नए कार्यों को हाथ में लिया है। जिसमें प्रमुख रूप से नगर पालिका को आत्मनिर्भर बनाने की मुहिम स्पष्ट परिलक्षित हुई है। अपनी आय के स्रोत बढ़ाने के लिए नगर पालिका के द्वारा व्यवसायिक दुकानों का निर्माण और उनकी नीलामी के साथ किराए के रूप में मिलने वाली बड़ी धन राशि से जिले की एकमात्र नगर पालिका अपने पैरों पर खड़े होने की कगार पर पहुंच गईहै। इस दौरान बैठक में उपाध्यक्ष रितेश गुप्ता, पार्षदगणों में संजय डोसी, विरेन्द्र बंसल, मंजू गोयल, पुष्पलता साहू, कुसुमलता राजवाड़े, गैबीनाथ साहू, राधामुनि सिंह, संतोष सोनी, सुरेन्द्र देवांगन, अजय सोनवानी, संजू सोनी, अजय सिंह, पुष्पलता पवन साहू, सहित समस्त पार्षद व मुख्य नगर पालिका अधिकारी मुक्ता सिंह चौहान सहित नपा अमले के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

50 लाख रूपए वार्षिक किराया का रचा कीर्तिमान

नपा अध्यक्ष केके अग्रवाल की कार्य योजना में गत वर्षो में बनी दुकानों के माध्यम से करोड़ो रूपए की आय दुकान नीलामी से मिलने के साथ नपा को अनुमानित 50 लाख रूपए वार्षिक किराए के रूप में मिलने की शुरूआत अब हो गई है। नपा अध्यक्ष ने इस पहल को और आगे बढ़ाने की मुहिम से अवगत कराते हुए कहा कि नगर पालिका के स्वयं की आय वार्षिक 02 करोड़ करने की कार्य योजना बनी है। जिससे नगर पालिका पूर्णतः आत्मनिर्भर होगी।

26 करोड़ से उपर के कार्यों की गिनाई उपलब्धि

बीते वर्ष के बजट में किए गये प्रावधानों के साथ नपा अध्यक्ष केके अग्रवाल ने बताया कि स्वीमिंग पुल, शॉपिंग कॉम्पलेक्स, रंगमंच संधारण, नपा स्वावलंबन योजना, हाट बाजार, सर्व समाज मांगलिक भवन, पौनी पसारी, पाथ-वे व फुटपाथ निर्माण, चारदीवारी, फेंसिंग कार्य, सड़क चौड़ीकरण, प्राईमरी स्कूल, बापू की कुटिया, विद्युत पोल विस्तार, पेयजल आपूर्ति हेतु पाईप लाईन विस्तार, सीसी व डामरीकृत सड़कें, आरसीसी नाली, कृष्णकुंज, सामुदायिक भवनों के संधारण के साथ नपा ने लगभग 26 करोड़ रूपए की राशि अर्जित कर इन विकास कार्यो को अंजाम तक पहुंचाया है।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह कार्यक्रम में 247 वर-वधुओं ने लिए फेरे

-संवाददाता-
कोरबा, 15 मार्च 2024
(घटती-घटना)।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत जिले के पोड़ी उपरोड़ा विकासखण्ड के पसान मिनी स्टेडियम मैदान में सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। योजनांतर्गत 247 वर-वधू के जोड़े दांपत्य सूत्र में बंधे और सुखमय जीवन का संकल्प लेकर एक नई जिंदगी की शुरूआत की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वाणिज्य उद्योग व श्रम मंत्री छत्तीसगढ़ शासन लखन लाल देवांगन शामिल हुए। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष शिव कला छत्रपाल सिंह कंवर, जनपद अध्यक्ष पोड़ी उपरोड़ा संतोषी पेन्द्रों, ग्राम पंचायत पसान सरपंच विनीता देवी तंवर, अपर कलेक्टर अनुपम तिवारी, एसडीएम सरोज महिलांगे सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं विभिन्न समाज के पदाधिकारी व नागरिकगण बड़ी संख्या में वर-वधुओं को आशीर्वाद देने उपस्थित रहे। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री देवांगन सहित अन्य अतिथियों ने सभी वर-वधुओं को सुखमय जीवन

का आशीर्वाद दिया।

कैबिनेट मंत्री देवांगन ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि यह खुशी की बात है कि जिले में सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया है, जिसमें वर वधुओं का सामाजिक, धार्मिक रीति-रिवाज का पालन करते हुए सामूहिक विवाह संपन्न कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह सौभाग्य है की बात है कि मां मातीन दाई के क्षेत्र में 247 जोड़ो का सामूहिक विवाह सम्पन्न हो रहा है और सभी जोड़ो को मातिन दाई के आशीर्वाद के साथ ही अपने माता पिता, परिवारजन सहित कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न समाज के लोगों, वरिष्ठजनों का शुभ आशीष मिल रहा है। उन्होंने परिणय सूत्र में बंधकर नव दाम्पत्य जीवन मे प्रवेश करने वाले वर-वधुओं के सुखमय जीवन की कामना करते हुए कहा कि आप सभी समाज के लिए प्रेरणा बनें एवं आदर्श जीवन यापन करें। इस दौरान मुख्य अतिथि मंत्री देवांगन सहित अन्य अतिथियों में नवदम्पतियों को अपना आशीर्वाद प्रदान करते हुए भेंट स्वरूप प्रोत्साहन राशि का चेक एवं उपहार सामाग्री प्रदान किया और सुखमय वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ महिला कोष अंतर्गत सिद्धि स्व सहायता समूह व मातिन दाई स्व सहायता समूह को 1-1 लाख रूपए का चेक भी प्रदान किया गया।

पति द्वारा पत्नी के 75 हजार,गहने और समान हड़प लिए जाने पर आयोग ने एफआईआर दर्ज करने दिया आदेश

-संवाददाता-
कोरबा, 15 मार्च 2024
(घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक एवं सदस्य श्रीमती अर्चना उपाध्याय ने जिला कलेक्टर कोरबा सभा कक्ष में महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों पर जन सुनवाई की। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक की अध्यक्षता में 248 वीं एवं कोरबा जिला की 07 वीं सुनवाई हुई। कोरबा जिले में आयोजित जनसुनवाई में कुल 36 प्रकरण सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान आज के प्रकरण दोनो पक्ष उपस्थित अनावेदक से 01 मई 2019 में विवाह किया था। विवाह के बाद पति ने आवेदिका के नाम पर 75 हजार रूपए का ऋण निकाला था।

पुरी राशि लेने के बाद आवेदिका को प्रताड़ित करने लगा। जिसका विस्तृत ब्यौरा आवेदिका ने अपने आवेदन पत्र में लिखा है। आवेदिका का पैसा छीनने के बाद आवेदिका का पति नशा करके मारपीट करने लगा और उसके प्रताड़ना के बाद आवेदिका का गर्भपात हो गया। तब वह छः माह मायके में रही। जिसके पश्चात् दोनो पक्ष को समझाईश पर आवेदिका अपने पति के साथ में रहने लगी। तब आवेदिका के पति ने सारे गहने व सामान गायब कर दिया और आवेदिका पर दोषारोपण करने लगा। महज 10 दिन के बाद तीनों अनावेदकगणों ने आवेदिका को दबाव डाला और पंचायत में बैठकर आवेदिका को एक कोरे पन्नें में तलाकनामा लिखवा दिया तथा 75 हजार रूपए के साथ लिए गए गहने और सामान भी वापस नहीं दिया। जिससे पीड़ित होकर आवेदिका ने आयोग में शिकायत दर्ज करायी। आयोग ने दोनो पक्ष को विस्तार से सुनने के पश्चात् यह पाया कि आवेदिका का पति 75000/- का लोन आवेदिका के नाम पर निकलवाया और उससे अपने घर में शौचालय बनवाया और बाकी रकम गहने आवेदिका से छीनकर अपने घर से निकाल दिया द्ध इस कार्य में आवेदिका के पति का पूरा परिवार सहयोग किया और शेष दो अनावेदक गांव के निवासी द्वारा कोरे कागज में शपथपत्र तथा तलाकनामा लिखकर आवेदिका को उसके मायके भिजवाया था द्ध जिस पर अनावेदक क्रमांक 2 और 3 ने अपनी गलती स्वीकारा और भविष्य में इस तरह से दोबारा कोरे कागज में तलाकनामा लिखवाने की गलती नहीं करेंगे कहते हुए आयोग से मांगा माफी तथा आश्वासन दिया कि आवेदिका के साथ थाना हरदी बाजार जा कर आवेदिका के पति और परिवार के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करने में सहयोग करेंगे। इस पर आवेदिका ने अपनी सहमति व्यक्त की है। इस प्रकरण में आयोग ने आवेदिका को अपने पति एवं परिवार के विरूद्ध थाना हरदीबाजार जा के केस धारा 498 (ए) भा.द.वि. एवं पैसा गबन करने के लिए घोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज करवाने की बात कही है। इस कार्य हेतु सखी वन स्टॉप सेंटर की केंद्र प्रशासक को निगरानी के लिये दिया गया है।

कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) अम्बिकापुर
जिला-सरगुजा,छत्तीसगढ़
-::संक्षिप्त निविदा प्रारूप::-

क्र. /आ.वि./निर्माण/2024/6917 / अम्बिकापुर,दिनांक.13/03/2024

छत्तीसगढ़ कार्य विभाग नियमावली 1983 आदिवासी विकास अन्तर्गत पीव्हीटीजी हितग्राही के लिये ग्राम आमादरहा वि0ख0 अम्बिकापुर में 01 नग आवास निर्माण कार्य (विद्युतीकरण एवं सेनेटरी कार्य सहित) इकाई लागत राशि रूपये 2.50 लाख के मान से मुहरबंद निविदाएं लोक निर्माण विभाग में उपयुक्त श्रेणी (द श्रेणी या उससे उपर) के पंजीकृत ठेकेदारों से लोक निर्माण विभाग के प्रचलित एस0ओ0आर0 के आधार पर कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास अम्बिकापुर जिला-सरगुजा (छ0ग0) में स्पीड पोस्ट के माध्यम से आमंत्रित की जाती है।

1.निविदा प्रपत्र हेतु आवेदन देने की अंतिम तिथि	- 10.04.2024 (अपरान्ह 05.30 बजे)
2.कोरे निविदा प्रपत्र क्रय करने की अंतिम तिथि	- 12.04.2024 (अपरान्ह 05.30 बजे)
3.निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	- 15.04.2024 (अपरान्ह 05.30 बजे)
4.निविदा खोलने की तिथि	- 16.04.2024 (अपरान्ह 12.00 बजे)

उपरोक्त प्रत्येक निविदा प्रपत्र का मूल्य रूपये - 750.00

निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन दिनांक 10.04.2024 अपरान्ह 5.30 बजे तक अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत किया जावे एवं उसके साथ निम्नानुसार दस्तावेज अनिवायत प्रस्तुत की जावे।
1. लोक निर्माण विभाग छ0ग0 में उपयुक्त श्रेणी में पंजीयन छायाप्रति।
2. निर्धारित राशि का चालान (नगद राशि स्वीकार्य नहीं की जावेगी)

यह निविदा मूल निविदा का एक अंग है, निविदा की अन्य शर्ते एवं कार्य की विस्तृत जानकारी अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखी जा सकेगी।

जी0नं0- 08547/2

सहायंक आयुक्त
आदिवासी विकास अम्बिकापुर

न्यायालय नजूल अधिकारी
अम्बिकापुर जिला सरगुजा,छ0ग0

रा.प्र.क्र. /अ-20(3)/2023-24

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक विनोद कुमार कंसल आ0 प्रेमचंद एवं 1 अन्य दोनो निवासी जनपद पारा अम्बिकापुर थाना व तहसील अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा छ0ग0 के द्वारा अपने संयुक्त स्वामित्व की मोहल्ला बाबूपारा नगर अम्बिकापुर शीट नम्बर 09 स्थित नजूल प्लाट नम्बर 3467/4866/234 रकबा 21×53=1113 वर्गफीट भूमि को बैक में बंधक रखने की अनापत्ति हेतु आवेदन पत्र मय शपथ पत्र, मेंटनें स खसरा की छायाप्रति के साथ पेश किया गया है।

अतः उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो वे अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 27/03/2024 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनाक 11/03/2024 को मेरे न्यायालयीन मुद्रा एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया।

सील

नजूल अधिकारी
अम्बिकापुर

न्यायालय तहसीलदार लखनपुर
जिला-सरगुजा,छत्तीसगढ़

ईश्तहार

लखनपुर, दिनांक- 14/03/2024

प्रति
समस्त ग्रामवासी
ग्राम-तुरना
तहसील-लखनपुर

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक रामू सिंह आ0 स्व0 ननका सिंह निवासी ग्राम तुरना तहसील लखनपुर के द्वारा अपने भतिजा स्व0 अशोक सिंह की मृत्यु दिनांक 17/10/2018 को हो जाने से (जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 की धारा 13(3) एवं छ0ग0 जन्म-मृत्यु रिज0 नियम 2001 के नियम 9 (3) के तहत मृत्यु प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन इस नयायालय में प्रस्तुत किया है जिस पर दिनांक 14/04/2024 को सुनवाई की जानी है।

आवेदक/आवेदिका के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से पेशी तिथी 14/04/2024 के पूर्व इस न्यायालय में आपत्ति पेश कर सकता है है। नियत दिनांक के पश्चात प्राप्त होने वाले दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

सील

तहसीलदार
लखनपुर,सरगुजा

व्हाइट बॉल क्रिकेट में नया नियम होगा लागू

» व्हाइट बॉल क्रिकेट में स्टॉप क्लॉक रूल होगा परमानेंट

» अगला ओवर शुरू करने के लिए मिलेंगे 60 सेकेंड; गलती पर 5 रन की पेनल्टी

नई दिल्ली, 15 मार्च 2024। लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट यानी वनडे और टी-20 फॉर्मेट में स्टॉप क्लॉक रूल परमानेंट होने जा रहा है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने फैसला लिया कि दोनों फॉर्मेट में टाइम मैनेज करने के लिए इस रूल को अप्लाय किया जाएगा।

स्टॉप क्लॉक रूल में बॉलिंग टीम को पारी का अगला ओवर शुरू करने के लिए 60 सेंकेड का टाइम मिलेगा। ऐसा नहीं करने पर टीम पर पेनल्टी लग जाएगी। आईसीसी के टी-20 वर्ल्ड कप के साथ यह रूल यूनिवर्सल हो जाएगा। यानी सभी तरह के व्हाइट बॉल क्रिकेट में इसे अप्लाय किया जाएगा।

हर तीसरी गलती पर 5 रन की पेनल्टी

फील्ड अंपायर 60 सेकेंड में ओवर शुरू करने के लिए 2 बार वॉर्निंग देगा। तीसरी बार गलती करने के बाद बॉलिंग टीम पर 5 रन की पेनल्टी लग जाएगी। फिर पारी में हर तीसरी गलती पर बॉलिंग टीम पर 5 रन की पेनल्टी लगती जाएगी। यानी एक वनडे पारी में अगर किसी टीम ने 9 बार ओवर शुरू करने में 60 सेकेंड से ज्यादा का समय लिया तो बैटिंग टीम के खाते में 15 रन जुड़ जाएंगे।

थर्ड अंपायर शुरू करेगा टाइमर

ओवर खत्म होने पर मैदान में लगी टीवी स्क्रीन पर 60 सेकेंड का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। थर्ड अंपायर कंट्रोल रूम से इसे शुरू करेगा। 60 सेकेंड का टाइम पार होने पर फील्ड अंपायर फील्डिंग टीम के कप्तान को वॉर्निंग देगा और हर वॉर्निंग का ध्यान भी रखेगा।

यह बिलकुल उस तरह होगा, जैसे इन दिन डीआरसी लेने के लिए दोनों ही टीमों को 15 सेकेंड का टाइम मिलता है। अपील होने के बाद थर्ड अंपायर स्टॉप क्लॉक शुरू कर देता है, जो मैदान की स्क्रीन पर नजर आती है। इसी को देखकर खिलाड़ी रिव्यू लेने के बारे में फैसला करते हैं।

टी-20 वर्ल्ड कप से परमानेंट होगा रूल

आईसीसी ने फैसला किया है कि जून में होने वाले टी-20 वर्ल्ड कप के साथ स्टॉप क्लॉक रूल परमानेंट हो जाएगा। अगर बैटर या डीआरसी के कारण ओवर शुरू करने में देरी हुई तो अंपायर के पास स्टॉप क्लॉक को रोकने का अधिकार भी होगा, ताकि फील्डिंग टीम पर बगैर गलती के पेनल्टी न लगे।

आईसीसी के बोर्ड मेंबर्स इस वक्त दुबई स्थित हेडक्वार्टर में मीटिंग कर रहे हैं। इसी मीटिंग में स्टॉप क्लॉक रूल को परमानेंट बनाने का फैसला किया गया। यह सिर्फ टी-20 ही नहीं, आईसीसी के वनडे फॉर्मेट में भी लागू होगा। दोनों ही फॉर्मेट में टाइम मैनेज करने के लिए इसे लाया गया। टेस्ट क्रिकेट में ओवर रेट पूरा नहीं करने पर टीमों के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पॉइंट्स काट लिए जाते हैं।

चैंपियंस ट्रॉफी के वेन्यू पर चर्चा नहीं

क्रिकबज की रिपोर्ट अनुसार, मीटिंग में 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी के वेन्यू पर डिस्कशन नहीं होगा। टी-20 वर्ल्ड कप खत्म होते ही चैंपियंस ट्रॉफी का मुद्दा गरमाने लग जाएगा, क्योंकि टूर्नामेंट की मेजबानी पाकिस्तान को मिली है और 2 बार की चैंपियन टीम इंडिया ने पॉलिटिकल कारणों के चलते यहां जाने से मना कर दिया है।भारत के मना करने के बाद ही पिछले एशिया कप को पाकिस्तानी की मेजबानी में श्रीलंका में कराना पड़ा था। भारत ने फाइनल समेत अपने सभी मैच श्रीलंका में ही खेले थे। टीम इंडिया ने टूर्नामेंट जीता भी था, जबकि मेजबान पाकिस्तान फाइनल में भी नहीं पहुंच सका था।

हॉकी इंडिया ने ड्रैग-फ्लिकर गोलकीपरों की अगली पीढ़ी को तैयार करने के लिए कार्यक्रम का अनावरण किया

नई दिल्ली, 15 मार्च 2024। देश में खेल की सर्वोच्च संस्था हॉकी इंडिया ने युवा ड्रैग-फ्लिकरों को लक्षित विशेष कोचिंग के माध्यम से भारतीय हॉकी के भविष्य में निवेश करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल की घोषणा की है। देश भर के गोलकीपर। यह रणनीतिक निर्णय जमीनी स्तर पर गोलकीपिंग और ड्रैग-फ्लिकिंग कोचिंग के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा के लिए बुलाई गई एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद लिया गया है। बैठक में एड्रियन डिसूजा, भरत छेत्री, योगिता बाली, हेलेन मैरी, दीपिका मूर्ति, आकाश चिकते, पीटी राव सहित भारत के प्रसिद्ध पूर्व गोलकीपरों के साथ-साथ भारत के प्रसिद्ध पूर्व ड्रैग-फ्लिकर रूपिंदर पाल सिंह, जुगराज सिंह, वीआर ने भाग लिया। हॉकी इंडिया की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, रघुनाथ, और गुरजिंदर सिंह।

अध्यक्ष दिलीप टिर्की, महासचिव भोला नाथ सिंह, कोषाध्यक्ष शेखर मनोहरन और हाई-परफॉर्मेंस निदेशक हरमन क्रूज़ सहित हॉकी इंडिया के अधिकारियों ने भी वस्तुतः बैठक में शामिल होकर विचार-विमर्श के बारे में अपनी जानकारी दी। नई पहल में ड्रैग-फ्लिकर और गोलकीपर के महत्वपूर्ण पदों पर प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान करने और उन्हें निखारने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ जमीनी स्तर पर प्रतिभा के पोषण पर सबसे अधिक जोर दिया गया है। कम उम्र से ही पोषण के माहौल को बढ़ावा देकर, हॉकी इंडिया का लक्ष्य देश की प्रतिष्ठित हॉकी टीमों के लिए प्रतिभा पाइपलाइन को मजबूत करना है।

संक्षिप्त खेल समाचार

आईपीएल 2024 के लिए सीएसके से जुड़े रविंद्र जडेजा

टूर्नामेंट में गेंद और बल्ले से मचाएंगे तूफान

नई दिल्ली, 15 मार्च 2024। आईपीएल का 17वां सीजन शुरू होने में कुछ ही समय बचा है। सभी खिलाड़ी अपनी-अपनी टीम से जुड़ रहे हैं। अब चेन्नई सुपर किंग्स के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा भी अपनी टीम से जुड़ गए हैं। जिसकी तस्वीर चेन्नई ने खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर की है। आईपीएल 2024 का पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा। ये मैच आरसीबी के लिए चेन्नई के खिलाफ जीतना बिलकुल भी आसान नहीं होगा। सीएसके के खिलाड़ी रविंद्र जडेजा अपनी तूफानी बल्लेबाजी और घातक गेंदबाजी से आरसीबी को परेशान कर सकते हैं।

मैथ्यू वेड रेड-बॉल प्रारूप से संन्यास लेने के लिए तैयार

सिडनी, 15 मार्च 2024। ऑस्ट्रेलिया के विकेटकीपर-बल्लेबाज मैथ्यू वेड ने मार्श शेफील्ड शील्ड फाइनल से पहले सबसे लंबे प्रारूप से संन्यास लेने के फैसले की घोषणा की । ऑस्ट्रेलिया के विकेटकीपर-बल्लेबाज मैथ्यू वेड ने रेड-बॉल क्रिकेट से संन्यास लेने के अपने फैसले की घोषणा की। वेड, जिन्होंने अपनी घरेलू टीम तस्मानिया के साथ शील्ड फाइनल में भाग लेने के लिए इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में अपना आगमन स्थगित कर दिया था, ने दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ संघर्ष से पहले अपने राज्य टीम के साथियों को अपनी पसंद के बारे में सूचित किया । वेड ने कहा , मैं अपने परिवार, अपनी पत्नी जूलिया और बच्चों विंटर, गोल्डी और ड्यूक को मेरे करियर के दौरान किए गए बलिदानों के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि मैंने एक रेड-बॉल क्रिकेटर के रूप में ऑस्ट्रेलिया और दुनिया की यात्रा की।

माही भाई से सीखने को बेकरार हूं

मुंबई, 15 मार्च 2024। भारत के आल राउंडर शार्दुल ठाकुर हाल में मुंबई के साथ रणजी ट्राफी खिताब जीतने के बाद आगामी इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के लिए महेंद्र सिंह धोनी की अगुआई में बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद लगाये हैं क्योंकि पिछला चरण उनके लिए इतना अच्छा नहीं रहा था। शार्दुल 2018 से 2021 तक सीएसके टीम का हिस्सा रहे थे जिसके बाद 2022 में वह दिल्ली कैपिटल्स और 2023 में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेले थे। इस सत्र में वह फिर सीएसके में वापसी करेंगे जिसके लिए उन्हें चार करोड़ रुपये में खरीदा गया।

शार्दुल ने एक साक्षात्कार में कहा, ''ईमानदारी से कहूं तो पिछला आईपीएल मेरे लिए अच्छा नहीं रहा। '' वह पिछले सत्र में 11 आईपीएल मैच में महज सात विकेट ही झटक सके थे और बल्ले से 14.13 के औसत से रन जुटा पाये थे। विदर्भ के खिलाफ गुरुवार को यहां मेजबान मुंबई के 169 रन की जीत से 42वां रणजी ट्राफी खिताब जीतने के बाद शार्दुल ने कहा, ''मैं माही भाई के नेतृत्व में खेलने को लेकर काफी उत्साहित हूं। जब आप उनके साथ खेलते हो तो आप मैच से कुछ न कुछ जरूर सीखते हो। वह स्टंप के पीछे खड़े होकर आपका मार्गदर्शन करते रहते हैं जिससे आपके प्रदर्शन में निखार आता है। '' ठाकुर ने कहा कि धोनी की सबसे अच्छी खासियत है कि वह एक खिलाड़ी के प्रदर्शन को निखरने देते हैं। इस आल राउंडर ने कहा, ''मुझे लगता है कि यह बहुत शानदार चीज है, वह खिलाड़ियों को काफी आजादी देते हैं और खिलाड़ियों को अपने प्रदर्शन की जिम्मेदारी खुद उठाने देते हैं। इसलिये मैं सीएसके में फिर से वापसी को लेकर काफी उत्साहित हूं। मैं कहूंगा कि मैं ऐसी टीम के लिए खेल रहा हूं जो परिवार और पारिवारिक संस्कृति को महत्व देती है। ''

ठाकुर के अलावा इस सत्र में सीएसके में युवा समीर रिज्वी, न्यूजीलैंड के आल राउंडर डेरिल मिचेल और रचिन रविंद्र भी शामिल होंगे। ठाकुर ने 19 साल के मुशीर खान से काफी प्रभावित थे जिन्होंने रणजी फाइनल में मुंबई की दूसरी पारी में शतक जड़ा जिससे टीम ने विदर्भ को जीत के लिए 538 रन का विशाल लक्ष्य दिया। ठाकुर ने कहा, ''मुझे लगता है कि वह (मुशीर खान) जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहा है, मैदान पर जिस तरह योगदान दे रहा है, क्षेत्ररक्षण और गेंदबाजी कर रहा है, उसे देखते हुए लगता है कि वह रणजी ट्राफी या आईपीएल जैसे उच्च स्तर के क्रिकेट में खेलने के लिए काफी परिपक्व हो चुका है।

लुंगी एनगिडी भी हुए बाहर

नई दिल्ली, 15 मार्च 2024। दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी को चोट लग गई है और वह आईपीएल 2024 में नहीं खेल पाएंगे। दिल्ली कैपिटल्स ने उनके स्थान पर ऑलराउंडर जेक फ्रेजर-मैक्गर्क को टीम में शामिल किया है।

एनगिडी ने 14 आईपीएल मैच खेले हैं और उनके नाम 25 विकेट हैं। वो पीठ के निचले हिस्से में चोट के कारण आईपीएल 2024 से बाहर हो गए हैं।एंगिडी आईपीएल के नए सीजन से पहले बाहर होने वाले दिल्ली कैपिटल्स के दूसरे खिलाड़ी हैं। इससे पहले हैरी ब्रूक ने भी अपना नाम वापस ले लिया था। ब्रूक फिट हैं लेकिन निजी कारणों की वजह से उन्होंने टूर्नामेंट से हटने का फैसला किया।क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने शुक्रवार को जारी एक बयान में कहा, प्रोटियाज तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी को दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल 2024 के लिए रिलीज कर दिया है। वह पीठ के निचले हिस्से की चोट से उबर रहे हैं। 27 वर्षीय खिलाड़ी को पिछले महीने एसए20 के प्लेऑफ के दौरान चोट लगी थी। एनगिडी फिलहाल क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका (सीएसए) की मेडिकल टीम की देखरेख में हैं और अपनी टीम, मोमेंटम मल्टीप्ली टाइटन्स के साथ पुनर्वास से गुजर रहे हैं।

फ्लैश टारगेट के चलते भारत की हुई किरकिरी

नई दिल्ली, 15 मार्च 2024। भारत को अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी समुदाय के सामने उस समय बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा जब प्रतिष्ठित डब्ल्यूएसपीएस पैरा विश्व कप ट्रैप स्पर्धाओं के फाइनल में 'फ्लैश टारगेट' को प्रतियोगिता के लिए उपयुक्त नहीं होने के कारण जूरी ने खारिज कर दिया। डब्ल्यूएसपीएस पैरा निशानेबाजी विश्व कप भारत में होने वाला अपनी तरह का पहला आयोजन है। इस प्रतियोगिता से निशानेबाजों को पेरिस पैरालंपिक के लिए 20 कोटा मिलने का प्रावधान है।कर्णी सिंह निशानेबाजी परिसर में संपन्न हुए इस आयोजन में 50 देशों के 250 से अधिक निशानेबाजों ने भाग लिया। शॉटगन स्पर्धाओं के फाइनल में हालांकि 'फ्लैश टारगेट' अनिवार्य नहीं हैं लेकिन उनका उपयोग ओलंपिक, आईएसएसएफ विश्व कप, विश्व चैंपियनशिप, महाद्वीपीय चैंपियनशिप और यहां तक कि भारत की राष्ट्रीय चैंपियनशिप और ट्रायल में भी किया जाता रहा है। इससे जूरी को निर्णय करने में आसानी होती है। 'फ्लैश टारगेट' पर कारतूस लगने के बाद उससे गुलाबी रंग की पाउडर जैसी चीज हवा में उड़ती है।

आल इंग्लैंड चैम्पियनशिप से बाहर हुई सात्विक-चिराग की जोड़ी

नई दिल्ली, 15 मार्च 2024। भारत के सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की दुनिया की नंबर एक जोड़ी गुरुवार रात यहां आल इंग्लैंड बैडमिंटन चैम्पियनशिप के पुरुष युगल प्री क्वार्टरफाइनल से बाहर हो गयी।

मुल्तान सुल्तांस ने पेशावर जाल्मी को हराया

कराची, 15 मार्च 2024। मुल्तान सुल्तांस ने एकतरफा क्वालीफायर में पेशावर जाल्मी को सात विकेट से हराकर लगातार चौथे पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) फाइनल में प्रवेश किया। मुल्तान सुल्तांस ने 2021 में पीएसएल खिताब जीता था लेकिन पिछले दो चरण में उसे फाइनल में लाहौर कलंदर्स से हार मिली थी। बाबर आजम की अगुआई वाली पेशावर जाल्मी को सोमवार को होने वाले फाइनल में जगह बनाने का एक और मौका मिलेगा जब वह इस्लामाबाद यूनाईटेड और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के बीच शनिवार को होने वाले एलिमिनेटर की विजेता से भिड़ेगी।

मुल्तान सुल्तांस ने गुरुवार रात पेशावर जाल्मी को सात विकेट पर 146 रन ही बनाने दिये। फिर उसने सलामी बल्लेबाज यासिर खान (54 रन) और फॉर्म में चल रहे उस्मान खान (नाबाद 36 रन) की बदौलत 18.3 ओवर में तीन विकेट पर 147 रन बनाकर जीत हासिल की। पेशावर जाल्मी के गेंदबाज छोटे से स्कोर का बचाव करने में असफल रहे।

विजय देवरकोंडा और मृणाल ठाकुर की फैमिली स्टार का टीजर हुआ रिलीज

5 अप्रैल को होगी दुनियाभर में रिलीज

तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के लोकप्रिय अभिनेता विजय देवरकोंडा और मृणाल ठाकुर की आगामी फिल्म फैमिली स्टार का टीज़र रिलीज कर दिया गया है। इस फिल्म का निर्देशन पारसुरम ने किया है। यह फिल्म तेलुगु, तमिल और हिंदी भाषाओं में 5 अप्रैल को दुनियाभर में सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी। टीजर में रोमांस और एक्शन का तड़का देखने को मिल रहा है। विजय देवरकोंडा अपने स्टाइलिश लुक में नजर आ रहे हैं, वहीं मृणाल ठाकुर भी बेहद खूबसूरत लग रही हैं। टीजर में एक सच्चे फैमिली मैन (विजय देवरकोंडा) की कहानी दिखाई गई है-वह खाना बनाता है, प्यार करता है, जरूरत पडऩे पर गुंडों से लड़ता है -वह यह सब करता है। यह साबित होने के बाद कि विजय देवरकोंडा वास्तव में एक फैमिली स्टार हैं हमें मृणाल ठाकुर के कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। विजय और मृणाल एक बस स्टैंड पर मिलते हैं। वह विजय से उसे उसके कॉलेज तक छोडऩे के लिए कहती है। वह जवाब देता है, मेरे लिए पेट्रोल खरीदो, मैं तुम्हें जरूर छोड़ दूंगा। अभी के लिए इतना ही.मृणाल ठाकुर ने सोशल मीडिया पर टीजर शेयर किया और उन्होंने लिखा, मचअवेटेड फैमिली स्टार टीजर अब रिलीज हो गया है। 5 अप्रैल को सिनेमाघरों में. #फैमिलीस्टार #फैमिलीस्टार ऑनअप्रैल5 इस बीच विजय देवरकोंडा ने टीजर साझा किया और लिखा, यह 5 अप्रैल फैमिली स्टार। मेरे सभी प्यारे परिवारों के लिए फैमिली स्टार टीजऱ इस साल की शुरुआत में विजय देवरकोंडा ने फिल्म का एक पोस्टर शेयर किया और फिल्म की रिलीज की तारीख अनाउंस की थी। उन्होंने लिखा, 5 अप्रैल, 2024 को आ रहा हूं। पिछले साल दिवाली पर फैमिली स्टार के एक्टर्स ने अपने इंस्टाफैम को कुछ इस तरह विश किया था, हमारे परिवार की तरफ से आपके परिवार को शुभ दीपावली। इस छुट्टियों के मौसम से परे उत्सव की खुशियां दोगुनी करने के लिए, फैमिली स्टार का पहला सिंगल बहुत जल्द आ रहा है।

संदीपा धर ने ब्लैक आउटफिट में गिराई बिजली, यूजर्स हुए घायल

बॉलीवुड अभिनेत्री संदीपा धर ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें वह बेहद खूबसूरत लग रही हैं। इन तस्वीरों में संदीपा को ब्लैक कलर की स्टाइलिश ड्रेस में देखा जा सकता है, जो उनके फिगर को काफी कॉम्पलिमेंट दे रही है। उनका लाइट मेकअप और खुले बाल उनके पूरे लुक को और भी निखार रहे हैं। साथ ही, उन्होंने खूबसूरत गोल्डन इयररिंग्स भी पहने हुए हैं। इन तस्वीरों को शेयर करते हुए संदीपा ने लिखा, काले कपड़े पहने लाल झंडा. उनकी तस्वीरों को इतना प्यार मिल रहा है कि कैप्शन की जरूरत ही नहीं है। कुछ ही घंटों में इन तस्वीरों को हजारों लाइक्स और कमेंट्स मिल चुके हैं। यूजर्स संदीपा के लुक की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। कुछ यूजर्स ने उन्हें ब्यूटीफुल, स्टनिंग और गॉर्जियस जैसे कमेंट्स किए हैं। तो वहीं कुछ ने उनके ड्रेस और मेकअप की भी तारीफ की है। साथ ही उनकी हॉटनेस की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं।

मुंह में बीड़ी और कांधे पर गमछा, भैया जी से मनोज वाजपेयी का भौकाली फर्स्ट लुक आउट

मनोज बाजपेयी बॉलीवुड सबसे ज्यादा टैलेंटेड और वर्सेटाइल एक्टर्स में से एक हैं। उन्होंने बॉलीवुड में तमाम फिल्मों में अपनी दमदार एक्टिंग का लोहा मनवाया है। वहीं मनोज बाजपेयी का ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी डंका बजता है। फैंस मनोज की हर फिल्म और सीरीज का ब्रेसब्री से इंतजार करते हैं। वहीं एक्टर अब जल्द ही भैया जी बनकर बड़े पर्दे पर छाने वाले हैं। एक्टर की इस अपकमिंग फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस हो गई है। मनोज बाजपेयी ने अपनी अपकमिंग फिल्म भैया जी' की रिलीज डेट का आज ऐलान कर दिया है। मनोज बाजपेयी की यह फिल्म 24 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी और इसका टीजर 20 मार्च की दोपहर को जारी किया जाएगा। अभिनेता ने सोशल मीडिया पर फिल्म का एक नया पोस्टर शेयर कर इसकी अनाउंसमेंट की है। मनोज ने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर हिंदी में लिखा, आ गए हैं वो. उन्होंने आगे फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस करते हुए लिखा, भैयाजी 24 मई को सिनेमाघरों में. टीज़र 20 मार्च को दोपहर 2:42 बजे रिलीज़ होगा। नए पोस्टर में, मनोज बिल्कुल ठेठ गांववाले के गेटअप में दिख रहे हैं। वे कुर्ता-धोती और गमछा लिए हुए दिख रहे हैं वहीं उनके मुंह में सिगरेट भी है और माथे पर खून की एक लकीर भी है। बैकग्राउंड किसी विरोध-प्रदर्शन का लग रहा है। दिलचस्प बात ये है कि मनोज इस फिल्म से बतौर निर्माता डेब्यू करने जा रहे हैं। उनके साथ उनकी पत्नी शबाना भी इस फिल्म की निर्माता है। मनोज की सिर्फ एक बंदा काफी है' काफी हिट रही थी। इसके अलावा, मनोज को जोरम' और किलर सूप' में भी देखा गया था। अब उनके पास पाइपलाइन में द फैमिली मैन' की अगली किस्त है। फिलहाल एक्टर अपनी अपकमिंग फिल्म भैया जी' को लेकर एक्साइटेड हैं।

संक्षिप्त खबरें

13 आईएएस अफसरों का हुआ ट्रांसफर

रायपुर, 15 मार्च 2024 (ए)। गुरूवार देर रात प्रदेश के 13 अफसरों का ट्रांसफर हुआ है। इसमें कई असफर सचिव स्तर के है। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के मुताबिक अपर मुख्य सचिव गृह और जेल मनोज पिंगुआ को छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल और व्यापम अध्यक्ष के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया है।

आरएसएस प्रांतीय संचालक से ट्रेन में की गई मारपीट

बिलासपुर के स्कूली छात्रों ने दिया अंजाम

रायपुर, 15 मार्च 2024(ए)। पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांतीय संचालक से ट्रेन में मारपीट की घटना सामने आई है। मामले में जीरो में एफआईआर दर्ज कर रायपुर जीआरपी जांच में जुट गई है। आजाद हिंद एक्सप्रेस बी-4 में सवार आरएसएस प्रांतीय संचालक रवींद्रनाथ बनर्जी कोलकाता से नागपुर जा रहे थे। इस दौरान बिलासपुर के अग्रवाल परिवार के स्कूली छात्रों ने मारपीट की। घटना पर रायपुर जीआरपी ने बुधवार को धारा 294, 323, 34, 363, 392, 506 और 511 भादसं के तहत मामला पंजीबद्ध किया है।

छत्तीसगढ़ के आइपीएस अफसरों को किया इम्पैनल

रायपुर, 15 मार्च 2024(ए)। छत्तीसगढ़ कैडर के 2 आइपीएस सहित 47 आइपीएस अफसरों को केंद्र सरकार ने इम्पैनल किया है। 2005 बैच के अमरेश मिश्रा और राहुल भगत केंद्र में इंस्पेक्टर जनरल इम्पैनल हो गये हैं। आपको बता दें कि दोनों आइपीएस अफसरों अभी छत्तीसगढ़ में अहम ओहदा संभाल रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक आदेश आज जारी कर दिया गया है. इसके मुताबिक रायपुर के आईजी आइपीएस अमरेश मिश्रा को आईजी पद पर इमपैनलमेंट किया गया है, वे रायपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक हैं। इसके साथ ही उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य आर्थिक अपराध अंवेषण ब्यूरो और एंटी करप्शन ब्यूरो का पुलिस महानिरीक्षक बनाया गया है। इसी तरह आइपीएस राहुल भगत को भी आईजी पद पर इमपैनलमेंट किया गया है। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी राहुल भगत सीएम सचिवालय के सचिव हैं तथा नए विभाग सुशासन एवं अभिसरण विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। आइपीएसअमरेश मिश्रा जहां अभी रायपुर आईजी के साथ-साथ ईओडब्ल्यू/एसीबी चीफ का जिम्मा संभाल रहे हैं. तो वहीं राहुल भगत अभी मुख्यमंत्री के सचिव हैं।

राज्य सरकार के कर्मचारियों को मिला बड़ा लाभ

राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों का डीए चार फीसदी बढ़ाया

पेंशनरों को भी होगा लाभ

रायपुर, 15 मार्च 2024 (ए)। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज अधिकारी-कर्मचारियों तथा मीडियाबंधुओं के हित में पांच अहम फैसले लिये। इनमें अधिकारी-कर्मचारियों को सातवें वेतनमान पर चार प्रतिशत का महंगाई भत्ता देना भी शामिल है। इसका लाभ पेंशनरों को भी मिलेगा। महंगाई भत्ते की यह राशि एक मार्च 2024 की तिथि से मिलेगी।

राज्य के अधिकारी-कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के एरियर्स की अंतिम किश्त की राशि का भुगतान भी होगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रीमती निहारिका बारिक की अध्यक्षता में एक समिति भी बनाई है जो कर्मचारियों की समस्याओं के संबंध में समीक्षा करेगी और इनके निराकरण से संबंधी सुझाव शासन को प्रस्तुत करेगी। ग्राम पंचायत सचिवों को भी राहत देते हुए उनके 55 दिनों की हड़ताल अवधि का वेतन भुगतान करने का निर्णय लिया गया है। अर्जित अवकाश में यह हड़ताल अवधि समायोजित होगी। इन निर्णयों से होली के त्यौहार में कर्मचारियों के परिवारों में खुशियों के और भी रंग भर जाएंगे।

अब महंगाई भत्ता हुआ 46 प्रतिशत

महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य के कर्मचारियों को सातवें वेतनमान में 04 प्रतिशत महंगाई भत्ते में एवं पेंशनरों के महंगाई राहत में 04 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। यह महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत 1 मार्च 2024 से दिया जाएगा। इसके फलस्वरूप महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दर सातवें वेतनमान में 42 प्रतिशत से बढ़कर 46 प्रतिशत तथा छठवें वेतनमान में यह 230 प्रतिशत हो जाएगी। इस निर्णय से राज्य के 3 लाख 90 हजार कर्मचारी तथा 1 लाख 20 हजार पेंशनर लाभान्वित होंगे। इस निर्णय से राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों को प्रतिमाह 68 करोड़ रुपए तथा साल में 816 करोड़ रुपए का लाभ प्राप्त होगा।

सातवें वेतनमान के एरियर्स की अंतिम किश्त भी मिलेगी

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर अधिकारियों-कर्मचारियों की सातवें वेतनमान के एरियर्स की अंतिम किश्त प्रदान करने की घोषणा भी की।

हड़ताल अवधि का वेतन पंचायत सचिवों को मिलेगा

मुख्यमंत्री ने आज संवेदनशील निर्णय लेते हुए ग्राम पंचायत सचिवों को भी राहत दी। ग्राम पंचायत सचिव पिछले साल 16 मार्च 2023 से 9 मई 2023 तक कुल 55 दिन हड़ताल पर थे। मुख्यमंत्री ने बताया कि ग्राम पंचायत सचिवों की हड़ताल अवधि को उनके अर्जित अवकाश में समायोजित करते हुए उन्हें 55 दिनों का वेतन भुगतान किया जाएगा। इस निर्णय से राज्य शासन पर 70 करोड़ रुपए का व्यय-भार आएगा।

कर्मचारियों की समस्याओं पर बनी समिति

मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारी भाईयों ने बहुत सी मांगों और समस्याओं के संबंध में अपनी बातें हमसे साझा की हैं। हम उनकी समस्याओं का पूरी संवेदनशीलता से समाधान करेंगे। उन्होंने बताया कि इन समस्याओं के हल के लिए प्रमुख सचिव,पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रीमती निहारिका बारीक की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति बनाई है। समिति विभिन्न कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों से चर्चा कर शासन को कर्मचारी हित में उचित सुझाव देगी। इस समिति में अध्यक्ष के अलावा प्रमुख सचिव विधि एवं विधायी, सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, सचिव वित्त सदस्य होंगे और सचिव सामान्य प्रशासन विभाग (शासकीय कर्मचारी कल्याण शाखा) सदस्य सचिव होंगे।

छत्तीसगढ़ में रामलला दर्शन योजना के खिलाफ दायर की गई पिटीशन

याचिकाकर्ता ने बताया संविधान के खिलाफ

बिलासपुर, 15 मार्च 2024 (ए)। छत्तीसगढ़ सरकार की रामलला दर्शन योजना को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई गई है। याचिका में सरकार की योजना को संविधान के धर्म निरपेक्षता सिद्धांत के खिलाफ बताया गया है. मामले में हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा है।

दरअसल, राज्य शासन की ओर से छत्तीसगढ़वासियों के लिए रामलला के दर्शन की योजना शुरू की है जिसमें लोगों को अयोध्या धाम ले जाकर रामलला के दर्शन कराकर वापस लाया जाता है। बिलासपुर जिले के देवरीखुर्द निवासी याचिकाकर्ता लखन सुबोध ने इसे संविधान में दिए गए प्रावधानों के खिलाफ बताते हुए इस योजना को बंद करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। रामलला दर्शन योजना संविधान में निहित बातों और शर्तों के विपरीत है। उन्होंने धर्मनिरपेक्षता पर तर्क देते हुए योजना को बंद करने के लिए राज्य शासन को आदेशित करने का आग्रह किया है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की डिवीजन बेंच में हुई।

मामले की सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से कहा गया कि रामलला दर्शन योजना किसी धर्म या जाति के आधार पर नहीं की गई है। यह योजना धर्म या जाति के आधार पर फर्क भी नहीं करता है। यह प्रदेशवासियों के भ्रमण के लिए है. प्रदेश में रहने वाले उन गरीबों के लिए यह योजना लाभदायक है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जो धार्मिक यात्रा पर नहीं जा पाते। वे फ्री में अयोध्या पहुंच जाएंगे और रामलला के दर्शन कर वापस आ जाएंगे। मामले की सुनवाई के दौरान कहा गया कि यह राज्य सरकार का नीतिगत निर्णय है, जिस पर हाईकोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता। बता दें कि रामलला दर्शन की योजना राज्य सरकार के कैबिनेट का फैसला है। मामले में कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है।

हाईकोर्ट ने 215 अधिकारियों के ट्रांसफर पर लगाई रोक

रायपुर, 15 मार्च 2024 (ए)। राज्य सरकार की तरफ से जारी 215 तबादला आदेश हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। राज्य सरकार ने पिछले दिनों राज्य में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अधीक्षक भू अभिलेख, सहायक अधीक्षक भू अभिलेख और जनपद पंचायत सीईओ के 200 से ज्यादा तबादला किये थे, जिसमें नायब तहसीलदार के 79, तहसीलदार के 49, अधीक्षक भू अभिलेख के 5, सहायक अधीक्षक भू अभिलेख के 59 और जनपद पंचायत सीईओ के 23 अधिकारी शामिल थे। दरअसल राज्य सरकार ने केंद्रीय चुनाव आयोग के 23 फ़रवरी के पत्र को आधार बनाकर ये तबादले किये थे। हाईकोर्ट में इस तबादले के विरुद्ध 50 से ज्यादा याचिकाएं दायर की गयी थी। दरअसल भारत निर्वाचन आयोग ने 23 फरवरी को कर्मचारियों के तबादले को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया था।

जिसमें तबादले के संदर्भ में उल्लेख था कि वैसे अधिकारी या कर्मचारी जो एक ही संसदीय क्षेत्र में तीन वर्ष या उससे अधिक समय से पदस्थ हैं, उनका तबादला किया जाना है। आधार बनाकर राज्य सरकार ने तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अधीक्षक भू अभिलेख और सहायक अधीक्षक भू अभिलेख,ट्रायबल विभाग के सीईओ के तबादले किये। लेकिन भारत निर्वाचन आयोग ने कर्मचारियों व अधिकारियों के तबादले को लेकर 27 फरवरी को एक और निर्देश जारी किया।

लिहाजा याचिका में इस बात को आधार बनाया गया कि जब भारत निर्वाचन आयोग ने अपने पूर्व के निर्देश के बाद ट्रांसफर को लेकर नया निर्देश जारी किया है, लिहाजा पिछले निर्देश को आधार बनाकर किये गये तबादले अवैध हैं। जस्टिस एनके व्यास ने इस मामले की सुनवाई की। हालांकि सुनवाई के दौरान राज्य शासन की तरफ से जानकारी दी गयी, कि वो तबादला रद्द करने पर विचार कर रही है, लेकिन जब शासन की तरफ से इस आदेश को निरस्त नहीं किया गया, तो फिर हाईकोर्ट ने तबादला आदेश को निरस्त करने का आदेश दिया।

स्वास्थ्य विभाग के बर्खास्त 5 हजार कर्मी हुए बहाल

25 हजार कर्मियों को मिला रूका वेतन

रायपुर, 15 मार्च 2024 (ए)। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी-कर्मचारी 21 अगस्त 2023 से 12 सितम्बर 2023 तक हड़ताल में थे। इस अवधि का अवकाश व रूका वेतन स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के निर्देश पर जारी कर दिया गया है। इसका लाभ प्रदेश के लगभग 30 हजार स्वास्थ्य कर्मियों को मिला हैं। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य फेडरेशन ने स्वास्थ्य मंत्री को आभार व्यक्त किया है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य फेडरेशन के आंदोलन कर रहे कर्मचारियों का उस दौरान कार्यालय में अनुपस्थित रहने के कारण बर्खास्तगी व वेतन अस्वीकृत कर दिया गया था। फेडरेशन के पदाधिकारियों ने इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात की थी। स्वास्थ्य मंत्री ने मुलाकात के बाद स्वास्थ्य महकमे के अधिकारियों को इन विसंगतियों को दूर करने के निर्देश दिये थे। निर्देश के परिपालन में बर्खास्त पांच हजार कर्मचारियों को वापस सेवा में ले लिया गया है। साथ ही 25 हजार कर्मचारियों का अंदोलन के दौरान रूका वेतन भी स्वीकृत कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य फेडरेशन ने स्वास्थ्य मंत्री का निज निवास कार्यालय में गत दिवस सौजन्य भेंट कर धन्यवाद दिया है। आंदोलन के दौरान चिकित्सा शिक्षा विभाग के दो हजार कर्मचारियों के रूके हुये वेतन को देने का आदेश जारी नहीं किया गया हैं। फेडरेशन के पदाधिकारियों ने इन कर्मियों का भी वेतन जारी करने का निवेदन स्वास्थ्य मंत्री से किया हैं।

छत्तीसगढ़ के चार शहरों को मिली 240 सिटी बसों की स्वीकृति

रायपुर, 15 मार्च 2024 (ए)। शहरों में सार्वजनिक परिवहन के ढांचे को दुरुस्त करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा पीएम ई-बस सेवा योजना प्रारंभ की गई है। योजना के तहत राज्यों को शहरों की जनसंख्या के आधार पर बसों की संख्या निर्धारित की गई है जिसके अनुसार रायपुर को 100, दुर्ग-भिलाई को 50, बिलासपुर को 50 तथा कोरबा को 40, इस प्रकार कुल 240 ई-बसों की स्वीकृति प्राप्त हुई है। भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य के चार प्रमुख शहरों रायपुर,दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा को पीएम ई-बस सेवा योजना के तहत इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की मंजूरी दी है। यह घोषणा न केवल छत्तीसगढ़ के लिए एक गौरवपूर्ण क्षण है, बल्कि पूरे देश के लिए एक मील का पत्थर भी है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ और हरित भारत के सपने को साकार करने में एक महत्वपूर्ण कदम है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस मौके पर कहा कि राज्य में इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत से शहरी परिवहन में क्रांति आएगी। यह पहल हमें पर्यावरणीय संरक्षण के साथ-साथ नागरिकों को बेहतर परिवहन सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में एक कदम आगे ले जाती है। उन्होंने नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों को इस चैलेंज में सफल होने पर बधाई दी एवं भविष्य में और शहरों को भी इस योजना में शामिल करने के लिए प्रयास करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने कहा कि डबल इंजन की सरकार के कारण हम नवाचार और स्थिरता की नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। यह योजना हमारे नागरिकों के लिए एक उपहार है, जो न केवल पर्यावरण को बचाएगी, बल्कि हमारे जीवन को भी सुगम बनाएगी। ई-बसों का आगमन छत्तीसगढ़ के नागरिकों के लिए एक नई और स्वच्छ परिवहन सेवा का द्वार खोलेगी। इन बसों के शुरू होने से पर्यावरणीय प्रदूषण में कमी आएगी और शहरों की वायु गुणवत्ता में सुधार होगा। साथ ही ऊर्जा की बचत भी होगी।

उच्च शिक्षा विभाग में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू

रायपुर, 15 मार्च 2024 (ए)। प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू किया जा चुका है। राज्य मंत्रिपरिषद की 6 मार्च को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया था। अब सरकार ने इसे पूरे राज्य में लागू करने का फैसला ले लिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पूरे राज्य में लागू करने के संबंध में आज उच्च शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है।

पत्रकारों को न्याय दिलाने गृह सचिव की अध्यक्षता में बनेगी कमेटी

रायपुर, 15 मार्च 2024 (ए)। लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि पत्रकारों एवं मीडियाजगत से जुड़े लोगों के खिलाफ किए गए कथित गलत मामलों की जांच की जाएगी।

पत्रकारों से चर्चा के दौरान सीएम साय ने कहा की मीडिया जगत से जुड़े लोगों के खिलाउ उत्पीड़न की अनेक शिकायतें सामने आई थीं। हमारे मीडिया विभाग ने भी पत्रकारों के खिलाफ किये गये कथित झूठे मुकदमे एवं उत्पीड़न आदि की जानकारी देते हुए न्याय दिलाने मांग की थी।इस संबंध में हम गृह सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाने की घोषणा करते हैं। मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि इस कमेटी में पत्रकारों समेत अन्य सदस्यों को भी नियुक्त किया जाएगा।

चीफ इलेक्शन आफिसर रीना बाबा कंगाले ने ली पुलिस अधीक्षकों की बैठक

लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी

रायपुर, 15 मार्च 2024(ए)। लोकसभा चुनाव की घोषणा में अब देरी की कोई गुंजाइश नजर आ रही है, दो आयुक्तों की नियुक्ति हो गई है। इधर लोकसभा चुनाव में लॉ एंड आर्डर के संबंध में चीफ इलेक्शन आफिसर रीना बाबा कंगाले ने आज छत्तीसगढ़ के सभी पुलिस अधीक्षकों को रायपुर बुलाया है। न्यू सर्किट हाउस में एसपी की मीटिंग आज सुबह दस बजे से प्रारंभ हो गई है। सिर्फ नक्सल जिलों के एडिशनल एसपी आए हैं। बाकी सभी जिलों के एसपी कल रात ही रायपुर पहुंच गए थे।लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। दो-एक दिन में कभी भी चुनाव का ऐलान हो सकता है। सूत्रों का कहना है कि 17 मार्च याने रविवार को चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव का ऐलान कर सकता है। इसके पीछे तर्क यह दिया जा रहा है कि आज और कल चुनाव आयोग में कुछ अहम बैठकें रखी गई है। वरना आजकल में कभी भी घोषणा हो जाती।

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफसेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)